ikf{kd if=dk

संपादक

प्रभात झा, सांसद

कार्यकारी संपादक

डॉ. शिवशक्ति बक्सी

संपादक मंडल

सत्यपाल
संजीव कुमार सिन्हा

कला संपादक

धर्मेन्द्र कौशल
विकास सैनी

सदस्यता शुल्क

वार्षिक : 100/-
त्रि वार्षिक : 250/-

संपर्क

InL;rk : +91(11) 23005798
Qku (dk-) : +91(11) 23381428
QDl : +91(11) 23387887

ई-मेल
kamalsandesh@yahoo.co.in

प्रकाशक एवं मुद्रक : डा. नन्दकिशोर गर्ग द्वारा डा. मुकर्जी स्मृति न्यास, के लिए एक्सेलप्रिंट, सी-36, एफ.एफ. कॉम्पलेक्स, झण्डेवालान, नई दिल्ली-55 से मुद्रित करा के, डा. मुकर्जी स्मृति न्यास, पी.पी-66, सुब्रमण्यम भारती मार्ग, नई दिल्ली-110003 से प्रकाशित किया गया। सम्पादक - प्रभात झा

विषय-सूची

भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक 8 एवं 9 जनवरी 2011 को गुवाहटी असम में सम्पन्न हुई।

भाजपा राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक
श्री नितिन गडकरी का अध्यक्षीय भाषण.......... 6

प्रस्ताव
असम और पूर्वोत्तर की संवेदनशील स्थिति संबंधी प्रस्ताव.......... 15
राजनीतिक मामलों पर प्रस्ताव.......... 19

भाजपा राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक.......... 23

मोर्चा / प्रकोष्ठ
भाजयुमो : राष्ट्रीय एकता यात्रा : कोलकाता.......... 28

राज्यों से
dukVd % पंचायत चुनावों में भाजपा का परचम.......... 25
eè; izns'k % निकाय चुनाव में कमल खिला.......... 25

अन्य
प्रधानमंत्री को ज्ञापन.......... 30

कमल संदेश के सभी सुधी पाठकों को "गणतंत्र दिवस (26 जनवरी)" की हार्दिक शुभकामनाएं

संपादक के नाम पत्र...

आदरणीय महोदय,

कमल संदेश पाक्षिक जनवरी 1–15 प्राप्त हुआ। मुखपृष्ठ आकर्षक और दिशा देता है। भ्रष्टमंडल सरकार के खिलाफ जंग आवश्यक है। मैकाले पुत्रों की सरकार आजादी के बाद से ही अपने काले कारनामों को शुरूआत कर चुकी थी। मुंदड़ा कांड नेहरू शासन से जन्मा था।

कांग्रेस के काले कारनामों की करतूतें राष्ट्रघाती रही हैं। कहा जाये तो गलत न होगा कि कांग्रेस की स्थापना ही राष्ट्रभक्तों को दबाने के लिये की गयी थी। कितने ही क्रांतिवीरों को कांग्रेसी एजेंटों ने फिरंगियों से पकडवा दिया। कितने शूरवीरों को फांसी पर लटकवा दिया।

मुखपृष्ठ पर दस घोटालों का विवरण है। विगत वर्ष में दस घोटाले हुये। कोई भी घोटालेबाज जेल नहीं गया है। इसके विपरीत राष्ट्रवादी ताकतों पर आरोप लगाये जा रहे हैं। राहुल, सोनिया, दिग्विजय संघ और राष्ट्रद्रोही सिमी से तुलना कर रहे हैं। मैकाले पुत्रों की सरकार अंतिम सांस गिन रही है।

प्रदीप
विश्व संवाद केन्द्र
कानपुर

व्यंग्य चित्र

हमें लिखें..

सम्पादक के नाम पत्र

कमल संदेश

सादर आमंत्रित

आपकी राय एवं विचार

सम्पादक,
कमल संदेश
डॉ. मुकर्जी स्मृति न्यास, पीपी-66
सुब्रह्मण्य भारती मार्ग, नई दिल्ली-110003
ई-मेल:
kamalsandesh@yahoo.co.in

सम्पादकीय

संघर्ष पथ पर भाजपा

dkग्रेसनीत यूपीए सरकार की पूरी शासनावधि महाघोटालों और भ्रष्टाचार का घोर अंधकारमय युग है। अतः इससे मुक्ति दिलाने के लिए हमें सड़क पर आना होगा। संघर्ष के लिए तैयार रहना होगा। कांग्रेस भ्रष्टाचार का पर्याय बन चुकी है। भ्रष्ट कांग्रेस से देश त्रस्त है। हमें गांव–गांव जाकर यह बताना होगा कि अगर भारत को बचाना है तो कांग्रेस को सत्ता से हटाना होगा। यह आह्वान भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नितिन गडकरी ने गुवाहाटी में आयोजित पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक में प्रतिनिधियों से किया। श्री गडकरी ने आगे कहा कि कांग्रेसनीत यूपीए के प्रति जनता में बचा–खुचा जो जन–विश्वास था, वह भी उठ गया है। उन्होंने कांग्रेस द्वारा भगवा आतंकवाद व हिंदू आतंकवाद का शोर मचाने तथा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर प्रहार किए जाने की घोर निंदा की और कहा कि कांग्रेस भ्रष्टाचार के कुकृत्य से जनता का ध्यान हटाने के लिए समाज व देशतोड़क बयान दे रही है।

भ्रष्टाचार विकास में बाधक है। कांग्रेस ने दो अपराध किए, एक, भ्रष्टाचार के महारोग से भारत की सेहत खराब की और दूसरा, देश को विकास करने से भी रोका। राष्टीय कार्यकारिणी बैठक में भ्रष्टाचार के मुद्दे पर भाजपा का तेवर इसे निर्णायक मोड़ तक ले जाने की ओर दिख रहा था। राजनीतिक प्रस्ताव पारित कर भ्रष्टाचार से लड़ने का संकल्प लिया गया। लोकसभा में विपक्ष की नेता श्रीमती सुषमा स्वराज और राज्यसभा में विपक्ष के नेता श्री अरुण जेटली ने भ्रष्टाचार के मुद्दे पर जिस तरह से बातें सबके सामने रखीं, उससे यह साफ हो गया कि यह सब कांग्रेस अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी और प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह की जानकारी में है। भ्रष्टाचार के मसले पर कांग्रेस संगठन और कांग्रेसनीत यूपीए सरकार पूरी तरह से दोषी है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक में उत्तर–पूर्व राज्यों की राजनैतिक परिस्थितियों पर गहन चिंता व्यक्त की गई और इसके अध्ययन के लिए एक समिति बनाई गई तथा उत्तर–पूर्व विकास दस्तावेज की योजना बनाकर इस क्षेत्र के समग्र विकास की कल्पना की गई। यह एक सार्थक पहल है। बैठक में समापन उद्बोधन देते हुए भाजपा संसदीय दल के अध्यक्ष श्री लालकृष्ण आडवाणी ने कहा कि वर्ष 2010 भारत के इतिहास का निर्णायक मोड़ साबित होगा। उन्होंने आगे कहा हम भ्रष्टाचार के मुद्दे पर 2014 के चुनाव में जाएं और उसे जीतना अपना लक्ष्य बनाएं।

'भ्रष्टाचार' यूपीए का 'शिष्टाचार' बन चुका है। देश में घोटाले पर घोटाले हो रहे हैं लेकिन प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह और कांग्रेस अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी जन–धन की लूट पर चिंतित नजर नहीं आते। कांग्रेसनीत यूपीए का यह रवैया उसे बहुत महंगा पड़ सकता है। ■

भ्रष्टाचार का साम्राज्य है यूपीए : नितिन गडकरी

भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक 8 एवं 9 जनवरी, 2011 को गुवाहाटी (असम) में सम्पन्न हुई। बैठक में अध्यक्षीय भाषण देते हुए भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नितिन गडकरी ने 'भ्रष्टाचार और महंगाई' के मुद्दे पर कांग्रेसनीत यूपीए सरकार पर जमकर प्रहार किया। श्री गडकरी ने कहा कि प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह आंखें मूंदे हुए हैं और शायद अपने हाथ भी बांध रखे हैं। हम यहां अध्यक्षीय भाषण का पूरा पाठ प्रकाशित कर रहे हैं:–

vkदरणीय आडवाणीजी, मंच पर बैठे वरिष्ठ सहयोगियों और पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के मेरे सभी साथियों,

सर्वप्रथम, प्रयागज्योतिषपुर की इस वैभवपूर्ण भूमि पर आपका अभिनंदन करते हुए मैं आप सभी को नववर्ष की शुभकामनाएं देता हूं। हम इस समय देश के पूर्वी भाग में हैं। यह वह भूमि है, जहां पर सबसे पहले सूर्य उदय होता है। मुझे विश्वास है कि नये कैलेन्डर वर्ष के प्रथम दिन का सूर्य हम सभी देशवासियों के लिये नई आशाएं एवं नई आकांक्षाएं लाया है।

हमारी यात्रा के ६० वर्ष

मित्रों, नव वर्ष का आगमन मुझे इस तथ्य का स्मरण कराता है कि इस वर्ष भारतीय राजनीति में हमारी यात्रा के 60 वर्ष पूरे हो रहे हैं। 6 दशक पहले, वर्ष 1951 में जब भारतीय जनसंघ का भारत के राजनीतिक क्षितिज पर जन्म हुआ, तो बहुत से लोगों ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। डॉ॰ श्यामा प्रसाद मुकर्जी और दीनदयाल उपाध्याय जैसे हमारे महान नेताओं के बलिदान के कारण, हमने भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में अपना स्वयं का एक स्थान बनाया है। इन महान नेताओं द्वारा दिए गए विचार, उनके द्वारा निर्धारित संगठनात्मक कार्यकलापों के सिद्धांत और उनके द्वारा स्थापित आदर्श हमारे कार्यदर्शन का मुख्य आधार रहेगा। सर्वप्रथम, मैं इन सभी नायकों की स्मृति को प्रणाम करता हूं।

इस अवसर मैं आपसे अपील करता हूं कि जनसंघ के स्थापना दिवस 21 अक्तूबर को 'कृतज्ञता दिवस' के रूप में मनाएं। मैं अपनी सभी प्रदेश इकाइयों से उन सभी कार्यकर्ताओं का भव्य सत्कार समारोह आयोजित करने का अनुरोध करता हूं जो 1951 से हमारे साथ काम करते आ रहे हैं। हमें स्मरण रखना होगा कि इन कार्यकर्ताओं ने हमारी पार्टी को एक ठोस संगठनात्मक आधार दिया जिसके कारण हम इस लम्बी यात्रा को तय कर पाये हैं।

पूर्वोत्तर : प्रेरणाप्रद नायकों की भूमि

हम यहां पर महाबाहू ब्रह्मपुत्र के तट पर बैठे हैं। आगे कुछ कहने से पहले, मैं अपनी मातृभूमि के उन सभी महान सपूतों और सुपुत्रियों का अभिनंदन करता हूं, जो सामान्यरूप से पूर्वोत्तर भारत और विशेषरूप से असम से हैं। महाबाहू ब्रह्मपुत्र के तट पर और मां कामाख्या देवी के आशीर्वाद से मैं सर्वप्रथम, महापुरूष श्रीमंत शंकरदेव का अभिनंदन करता हूं, जिनका योगदान असम की उच्च सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत में अद्वितीय है। यह याद रखने योग्य है कि यह लछित बुरफुकन की भूमि है, जिनके ये शब्द ''देखत से माम डंगोर ना होये'' अमर हो गये। वह एक ऐसे महान योद्धा थे, जिसने विदेशी आक्रमणकारियों को असम में

घुसने से काफी लम्बे समय तक रोके रखा। कनकलता डेका से लेकर लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोलाई तक स्वतंत्रता–सेनानियों के अलावा, इस भूमि ने ऐसे अनेक महान नायक देश को दिये हैं जिनके योगदान को राष्ट्र कभी भी भुला नहीं सकता। हम सभी को समूचे पूर्वोत्तर भारत की विरासत पर गर्व है। मित्रों, मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि पूर्वोत्तर महान योद्धाओं, समाज सुधारकों, विकास कार्यकर्त्ताओं, कलाकारों और खिलाड़ियों की भूमि रही है। मिजोरम के खुआंग चेरा, अरूणाचल प्रदेश के डीइंग एरिंग, नागालैंड की रानी मां गाइदिल्यू, मणिपुर के राजकुमार टिकेन्द्रजीत, मेघालय के तीरथ सिंह, थुंगन संगमा तथा मेघालय के कींग नगबाह और त्रिपुरा के जीतेन पाल द्वारा किये गये महान कार्यों को कोई कैसे भुला सकता है? इस भूमि ने अनेक महान नायक पैदा किये हैं और भारत के शानदार इतिहास को समृद्ध बनाया है। कारगिल युद्ध के समय भी इस क्षेत्र से भारत माता के अनेक सपूत–सुपुत्रियों ने राष्ट्र के लिए सर्वोच्च बलिदान किया। असम के कैप्टन जिंतू गोगई से लेकर कैप्टन केझोक्यु केंगुरिसे–जैसे अनेक शहीदों ने बलिदान दिया। हम इन सभी को अपनी आदरांजालि प्रस्तुत करते हैं।

यह कितना हास्यास्पद है कि जब कांग्रेस अपनी स्थापना के 125 वर्ष का उत्सव मना रही थी, तब यूपीए वर्ष 2010 को घोटालों और भ्रष्टाचार का वर्ष मना रहा था। वास्तव में हर महीने एक नए घोटाले का पर्दाफाश हुआ। एक के बाद दूसरे घोटाले ने राष्ट्रमंडल खेलों के आयोजन को जनता के उपहास का विषय बना दिया।

हम सभी जानते हैं कि पूर्वोत्तर से अनेक खिलाड़ियों ने हाल ही सम्पन्न राष्ट्रमंडल खेलों तथा एशियाई खेलों में भारत के लिये अनेक पदक जीते हैं और भारतीय जनता पार्टी को उनकी उपलब्धियों पर गर्व है।

पूर्वोत्तर में भाजपा

मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब पहले जनसंघ और बाद में भाजपा ने पूर्वोत्तर में काम करना आरंभ किया, तो स्थिति बहुत ही कठिन थी। परन्तु हमारी कार्ययोजना में पूर्वोत्तर भारत का सदैव एक प्रमुख स्थान रहा है। इस अवसर पर हमें उन सभी का स्मरण करना चाहिए जिन्होंने इस क्षेत्र में पार्टी संगठन को मजबूत बनाने में उल्लेखनीय प्रयास किए। अतीत में हमारे वरिष्ठ नेताओं की श्रृंखला में नागालैण्ड के होशिके सेमा और एन.सी. झिलियांग, त्रिपुरा से शहीद श्याम हरी शर्मा और असम से रमेशजी मिश्रा प्रमुख रहे हैं। मणिपुर के शहीद मधुमंगलम शर्मा और असम के जयन्त दत्ता पार्टी तथा वैचारिक आंदोलन का काम करते हुए शहीद हो गए। पिछले दिनों ही बंसीधर सोनीजी जिन्होंने यहां काम किया, का निधन हो गया। हम उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं। असम में हम लखीधर गोहीन जैसे पार्टी कार्यकर्ताओं तथा हमारे वरिष्ठतम नेता पद्मनाभ आचार्यजी के योगदान को भुला नहीं सकते। पद्मनाभजी ने हाल ही में जीवन के 80 वसंत पूरे किए हैं और वह अभी भी सक्रिय हैं। मैं उनके और उन सभी के प्रति जिन्होंने इस क्षेत्र में पार्टी संगठन खड़ा करने में योगदान दिया, अपना आभार प्रकट करता हूं।

असम में तीस वर्ष पूर्व यद्यपि हम कोई बड़ी शक्ति नहीं थे, तथापि हमने बंगलादेशियों की घुसपैठ के विरूद्ध असम आन्दोलन का समर्थन किया था, क्योंकि हमारा यह मानना है कि असम के लोग समूचे राष्ट्र की एकता और अखण्डता के लिये लड़ रहे हैं। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि यह असम की ही भूमि है जिसने 1980 के शुरू में बंगलादेशी घुसपैठियों के मुद्दे पर ऐतिहासिक असम आन्दोलन में अपने अनेक युवा सपूतों एवं सुपुत्रियों को खोया। अनेक युवा कार्यकर्ताओं ने बड़ी बहादुरी से गोलियों का सामना किया और हमारी महान भारत माता की संप्रभुता बचाने के लिये अपना बलिदान दिया। उनके इस महान बलिदान के कारण ही आज हम यहां पर बैठक आयोजित कर सके हैं। मैं यहां पर इस बात का भी उल्लेख करना चाहूंगा कि भाजपा एवं हमारे समूचे वैचारिक आन्दोलन, जिसका हम एक अंग है ने असम में छद्म आक्रमण की समस्या से लड़ने का सदैव समर्थन किया है। इस संघर्ष में जिन लोगों ने अपने जीवन का बलिदान दिया है, उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए मैं यह दोहराना चाहता हूं कि दुनिया की कोई भी शक्ति हमें उन सभी घुसपैठियों का पता लगाने, मतदाता सूची में उनका नाम हटाने और उन्हें वापस भेजने से रोक नहीं सकती, जिन्होंने इस सुन्दर भूमि की नीली पहाड़ियों और हरी घाटियों पर कब्जा किया हुआ है। मुझे विश्वास है कि बिहार की तरह असम में भी लोग सुरक्षा और सुराज के लिये हमें अपना जनादेश देंगे। मैं असम के लोगों से सच्चे मन से अपील करता हूं कि वे भाजपा को एक अवसर दें। मैं उन्हें आश्वस्त करता हूं कि यदि हमें अवसर दिया जाता है, तो हमारी सरकार न केवल भविष्य में घुसपैठ को सख्ती से रोकेगी अपितु उन सभी को देश से बाहर निकाल भेजेगी, जो भारत के नागरिक नहीं हैं और यहां पर अवैध रूप से रह रहे हैं।

बिहार में हमारा शानदार परफोरमेंस

मैं आपको बिहार में हमारी जीत के महत्व के बारे में

भी बताना चाहूंगा। निश्चय ही यह कोई मामूली सफलता नहीं थी। 89 प्रतिशत की दर से जीत भारत के निर्वाचन इतिहास में एक ऐतिहासिक घटना है। इस सफलता के पीछे अनेक कारण हैं और हमें उन्हें ध्यान में रखना चाहिए। इस सफलता के लिए हमारे राज्य का नेतृत्व और सभी कार्यकर्ता बधाई के पात्र हैं। एकजुट पार्टी संगठन, निम्नतम स्तर पर माइक्रो प्रबंधन, उम्मीदवारों का सही चुनाव और सबसे ऊपर हमारी साख, जिसे हमने सुराज संबंधी मुद्दे को लेकर बड़ी मुश्किल से हासिल किया है, ये सभी इस सफलता के कुछ प्रमुख कारण हैं। मैं इस ऐतिहासिक जीत के लिए उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी और प्रदेशाध्यक्ष डॉ॰ सी॰पी॰ ठाकुर सहित सभी वरिष्ठ नेताओं को बधाई देता हूं। मैं बिहार के मुख्यमंत्री की भी प्रशंसा करता हूं जिन्होंने राजग की इस जीत में काफी बड़ा योगदान दिया है। गत जून में पटना में हुई हमारी बैठक के बाद हमारी अनेक प्रदेश इकाईयों ने विभिन्न चुनावों में शानदार जीत हासिल की है। जम्मू एवं कश्मीर में लद्दाख स्वायत क्षेत्र के चुनावों में पहली बार हमारे पांच उम्मीदवारों ने जीत हासिल की है। गुजरात, राजस्थान, मध्यप्रदेश में स्थानीय चुनावों में लोगों ने भाजपा में अपना भारी विश्वास व्यक्त किया है। केरल में भी हमने स्थानीय चुनावों में अपनी सीटों में बढ़ोतरी की है। कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश तथा अडंमान निकोबार और दादरा नगर हवेली में भी हमारी इकाइयों ने महत्वपूर्ण चुनावी जीत हासिल की हैं, जोकि बहुत ही संतोषजनक बात है।

यूपीए - २ : भ्रष्टाचार का साम्राज्य

यद्यपि हम निश्चित रूप से आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन हम आत्मसंतुष्ट होकर नहीं बैठ सकते। इस समय देश नेतृत्व के गंभीर संकट से जूझ रहा है और देश के लोग नेतृत्व प्रदान करने के लिए भाजपा की ओर देख रहे हैं जो उनकी आकांक्षाओं को साकार कर सके। यूपीए–2 के 20 महीने का शासन घोर त्रासदी सिद्ध हुआ है। प्रतिदिन देश को एक नया घोटाला देखने को मिल रहा है। खेलों से नागरिक आपूर्ति तक और दूरसंचार से नागर विमानन तक यूपीए–2 ने घोटालेबाजों को शासन के हर क्षेत्र में लूटमार करने की छूट दे दी है। यद्यपि लूटमार करने वाले सरकारी खजाना खाली कर रहे थे, तब प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह अपनी आंखें बंद करके खड़े रहे और संभवतः हाथ भी बांध रखे थे।

यह कितना हास्यास्पद है कि जब कांग्रेस अपनी स्थापना के 125 वर्ष का उत्सव मना रही थी, तब यूपीए वर्ष 2010 को घोटालों और भ्रष्टाचार का वर्ष मना रहा था। वास्तव में हर महीने एक नए घोटाले का पर्दाफाश हुआ। एक के बाद दूसरे घोटाले ने राष्ट्रमंडल खेलों के आयोजन को जनता के उपहास का विषय बना दिया। राष्ट्र के रूप में हमारे खिलाड़ियों के शानदार प्रदर्शन से हम अपनी कुछ प्रतिष्ठा बचा सके। इसके तुरंत बाद आदर्श सोसायटी घोटाला सामने आया। एक मुख्यमंत्री, जिन्हें नवम्बर 2009 में मुम्बई पर आतंकवादी हमले के बाद लाया गया था, को एक ऐसे घोटाले के लिए अपना त्याग–पत्र देना पड़ा जिससे यह पता चला कि सत्तारूढ़ दल की बड़ी हस्तियों और नौकरशाहों द्वारा सुरक्षा संबंधी मानदंडों की किस प्रकार अवहेलना की गई! 2जी–3जी घोटाला तो वास्तव में सभी घोटालों से ऊपर उठकर अपनी चरम सीमा तक पहुंच गया। इस महाघोटाले में जितनी भारी धनराशि की लूट की गई है वह कुछ राज्यों के बजट परिव्यय के लगभग बराबर है।

हमें स्मरण रखना चाहिए कि ये घोटाले इतने बड़े हैं कि सरकारी एजेंसियां और विभाग चाहें तो भी उन्हें दबा नहीं सकते। न्यायपालिका को भी उनकी दखल लेनी पड़ रही है। सभी घोटाले इतने गंभीर हैं कि उन्हें विपक्ष का प्रोपेगण्डा भी नहीं कहा जा सकता। यह वास्तविकता है और अब कोई भी संलिप्त अपराधियों को बचा नहीं सकता। इतने घोटालों का पता चलने के बाद भी यूपीए नेता बड़ी बेशर्मी से 'भ्रष्टाचार तनिक भी बर्दाश्त न करने' की दुहाई दे रहे हैं।

हमारा यह दृढ़ मत है कि ये घोटाले न केवल व्यवस्थागत असफलताओं का प्रमाण है बल्कि एक प्रकार से गुमराह करने वाले भी हैं। ये घोटाले एक किस्म से राष्ट्रीय खजाने की सुनियोजित लूट जैसे हैं। जिस तरीके से यूपीए सरकार ने लोकसभा में विपक्ष की नेता श्रीमती सुषमा स्वराज द्वारा उठाई गई आपत्तियों को अनदेखा करते हुए वर्तमान मुख्य सतर्कता आयुक्त की नियुक्ति की है, उससे सभी भ्रष्ट व्यक्तियों को व्यवस्थित रूप से सुरक्षा प्रदान करने के सत्ताधारियों के विशेष इरादे का पता चलता है। यह व्यवस्था को नष्ट कर निजी इरादों को पूरा करने के अलावा कुछ नहीं है। बोफोर्स मामले में हाल में हुए रहस्योद्घाटन यूपीए को यह याद दिलाने के लिए काफी हैं कि कोई व्यक्ति हर समय सभी व्यक्तियों को मूर्ख नहीं बना सकता। अब राजस्व विभाग ने निर्णायक रूप से यह सिद्ध कर दिया है कि इस मामले में रिश्वत दी गई और प्राप्त की गई; अतः यदि यह सरकार सत्यनिष्ठा और उत्तरदायित्वता के प्रति गंभीर है, तो इसे तुरंत विशेष जांच टीम नियुक्त करने के लिए उच्चतम न्यायालय में जाना चाहिए। उपदेश, बहुसूत्री कार्यक्रमों की घोषणा और अपने ही द्वारा नियुक्त राजनीतिक लोगों को खोखली अपील करने से कोई लाभ नहीं होने वाला। जरूरत इस बात की है कि कुछ विश्वसनीय कदम उठाए जाएं जो

दृढ़संकल्प से लेकर अपराधियों को दंडित करने वाले हों। इस मामले में देश का कानून अस्पष्ट है। प्रथम दृष्टया साक्ष्य ध्यान में रखकर कानून लागू करने वाली एंजेसियों को एफ. आई. आर. दर्ज करानी चाहिए। उन्हें संदिग्ध व्यक्तियों को गिरफ्तार करके उनसे पूछताछ करनी चाहिए और साक्ष्य एकत्रित करना चाहिए और निर्धारित अवधि के भीतर चार्जशीट फाइल करनी चाहिए। यह कोई नहीं जानता कि ऐसा अभी तक क्यों नहीं हुआ।

लोग यूपीए से कुछ साधारण से प्रश्न पूछना चाहते हैं: आप जे॰पी॰सी॰ से क्यों घबरा रहे हैं? आपको किस बात का डर है? तुलमोहन रामों और नागरवालों से लेकर वारेन एंडरसनों और ओटावियो क्वात्रोचियों तक सभी अपराधी किस प्रकार दंडित होने से सदैव बचते रहे? यह मात्र भ्रष्टाचार के प्रकरण नहीं है। ये इस बात के उदाहरण भी हैं कि किस प्रकार एक के बाद दूसरी कांग्रेस सरकार ने उन लोगों की पीठ में छुरा घोंपा है, जिन्होंने अपने हितों की रक्षा के लिए उन्हें चुना था।

यदि प्रधानमंत्री को अपने पर इतना भरोसा है कि वह अपराधी नहीं है, तो वह जे॰पी॰सी॰ की वैध मांग का विरोध करने के लिए इस प्रकार क्यों अड़े हुए हैं? इस प्रकार की हठधर्मिता आपातकाल पूर्व दिनों की याद दिलाती है। भाजपा इस रवैये की निंदा करती है और सरकार को चेतावनी देती है कि इस प्रकार के टकराव का रवैया सरकार को बहुत महंगा पड़ सकता है।

यदि प्रधानमंत्री को अपने पर इतना भरोसा है कि वह अपराधी नहीं है, तो वह जे॰पी॰सी॰ की वैध मांग का विरोध करने के लिए इस प्रकार क्यों अड़े हुए हैं? इस प्रकार की हठधर्मिता आपातकाल पूर्व दिनों की याद दिलाती है। भाजपा इस रवैये की निंदा करती है और सरकार को चेतावनी देती है कि इस प्रकार के टकराव का रवैया सरकार को बहुत महंगा पड़ सकता है। यही हठधर्मिता संसद में गतिरोध का कारण है। इस गतिरोध के लिए विपक्ष जिम्मेदार नहीं है बल्कि स्पष्ट तौर पर सरकार ही जिम्मेदार है। इस मुद्दे पर समूचा विपक्ष एकजुट है और जितनी जल्दी सरकार हमारी मांग स्वीकार करती है उतना ही सभी के लिए अच्छा होगा।

शासन में पारदर्शिता और उत्तरदायित्व

हम सभी भ्रष्टाचार के आयामों से परिचित हैं। भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए जो सबसे जरूरी बात वह है इस बुराई को समाप्त करने के लिए राजनीतिक इच्छा का होना। राजग शासन के दौरान इस राजनीतिक इच्छा के कारण हमने राज्य सरकारों के मंत्रिमंडल के मंत्रियों की संख्या सीमित करने का प्रयास किया था ताकि पद का दुरूपयोग न हो सके। मेरी यह सुविचारित राय है कि हम सभी को एक ऐसी प्रणाली अपनानी चाहिए जो सही नैतिक मूल्यों को अपनाने के लिए लोगों को प्रोत्साहित करे। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हमें नवोन्मेषी और परिणामोन्मुखी उपायों के साथ कार्य करना होगा।

भाजपा का यह मानना है कि चुनाव संबंधी खर्च इस समस्या का मूल प्रमुख कारण है। इस समस्या का समाधान करने की दृष्टि से हमने आजीवन सहयोग निधि नामक एक नया जीवनभर निधि–एकत्रीकरण कार्यक्रम आरंभ किया था। हमें प्रसन्नता है कि हम इस कार्यक्रम को लागू करने में काफी हद तक सफल हुए हैं और इसके साथ–साथ हमने पार्टी के लिए चुनावी फंड में बढ़ोतरी करने के लिए एक पारदर्शी तरीके से एकत्रित विशेष सहयोग निधि की भी स्थापना की है। शासन के मामले में भी हमारी सरकारें अधिक पारदर्शिता और उत्तरदायित्व लाने का प्रयास कर रही हैं ताकि भ्रष्टाचार को समाप्त किया जा सके। हमने अपनी सभी राज्य सरकारों को ई–टेंडर प्रणाली लागू करने के लिए कहा है और हम स्वच्छ और भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन देने के लिए विभिन्न उपायों को लागू करने हेतु चर्चा कर रहे हैं। मैंने गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री और सुशासन प्रकोष्ठ के संयोजक, मनोहर परिकर से अनुरोध किया है कि वह एक अध्ययन दल गठित करे जो इस संबंध में अपनी सिफारिशें दें। मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि हम अपनी सभी राज्य सरकारों से अनुरोध कर रहे हैं कि वे प्रशासन में और अधिक पारदर्शिता और उत्तरदायित्व लाने के उद्देश्य से ई–शासन विभाग गठित करने की संभावना पर विचार करें। मैं अपने संकल्प को दोहराना चाहूंगा कि अपराधी को किसी भी हाल में छोड़ा ना जाए। हमारे विरोधी भाजपा की छवि खराब कर सकते हैं, परंतु मेरा यह मानना है कि ऐसा करने से उनको अपने घोटालों को छिपाने में कोई मदद नहीं मिलेगी।

आतंकवाद : यूपीए का दयनीय रिकार्ड

आतंकवाद से लड़ने के मामले में यूपीए का रिकार्ड भी बहुत दयनीय है। कश्मीर के मामले में तथाकथित वार्ताकार अपने लक्ष्य के प्रति अस्पष्ट और दिग्भ्रमित हैं। उनके लिए कोई टर्म ऑफ रिफरेंसस् निर्धारित नहीं है और इसी कारण उनका कार्य दिशाहीन बन गया है। यही दिशाहीनता नक्सली समस्या के बारे में भी व्याप्त है। यद्यपि भाजपा में हम सभी और हमारे सभी मुख्यमंत्री नक्सली समस्या से लड़ने के लिए

एक समान रणनीति और समेकित प्रयासों की सतत् मांग कर रहे हैं, तथापि यूपीए आतंक संबंधी प्रत्येक मुद्दे पर अलग–अलग बोलियों में बोल रहा है। सत्तारूढ़ दल के अंदर ऐसे तत्व विद्यमान है, जो नक्सलियों के साथ मिले हुए हैं और उन लोगों की पीठ थपथपा रहे हैं, जो भारत को जम्मू कश्मीर में अतिक्रमणकारी मानते हैं और तथाकथित हिन्दू आतंकवाद का मुद्दा उठाकर बहुसंख्यक समुदाय की भावनाओं से खेलने का प्रयास कर रहे हैं। क्या हमें यूपीए नेताओं से एक बुनियादी स्तर पर परिपक्वता की आशा नहीं करनी चाहिए? क्या वे एक ग्रुप की धमकियों को अनदेखा करके दूसरे को दानवी शक्ति बताकर आतंक के विरूद्ध हमारी लड़ाई को कमजोर नहीं कर रहे? क्या यूपीए के कुछ नेता इतने संवेदनहीन और गैर–जिम्मेदार हो सकते हैं कि जो आधी अधूरी जांच के आधार पर ही विदेशी राजनयिकों के साथ अपने विचार विमर्श के दौरान पक्षपातपूर्ण रवैये से आतंकवाद के प्रति अपने विचार व्यक्त करें? हमारे सभी देशवासी इस बात को लेकर अत्यधिक चिंतित हैं कि यूपीए के कुछ नेताओं के इस प्रकार गैर–जिम्मेदाराना वक्तव्यों से भारत का पक्ष कमजोर पड़ता है और सीमापार के लोगों का हौंसला बढ़ता है। दुर्भाग्यवश, यूपीए गलत संकेत देने का कोई भी अवसर नहीं गंवाता। जबकि समूचा राष्ट्र सरकार से यह आशा लगाए हुए है कि वह अफजल गुरू, जो संसद हमले के मामले में दोषी है, को जल्द फांसी दी जाए। वहां यूपीए ने शौकत गुरू, जो इस मामले में अफजल गुरू का साथी था, को अपने कारावास की अवधि पूरा होने से लगभग एक वर्ष पहले छोड़ दिया है। जिसका कारण वह उसका 'अच्छा आचरण' बताते हैं! यह जनमत की घोर उपेक्षा की पराकाष्ठा है। क्या यह आतंकवाद के विरूद्ध सरकार की नरम और गैर–जिम्मेदाराना दृष्टिकोण का प्रकटीकरण नहीं है?

इस मौके पर, हम सरकार से मांग करते हैं कि वह सन् 2004 से अब तक हुए आतंकवादी हमलों से जुड़ा समूचा डाटा प्रकाशित करे और बताए कि कितने मामलों में जांच पूरी हो गई है; कितनों में केस दायर हो गए हैं और कितने दोषियों को दण्ड दिया जा चुका है। राष्ट्र यह भी जानना चाहेगा कि किसी न किसी रूप में आतंक का शिकार बने लोगों को सरकार ने राहत और पुनर्वसन के लिए कितनी सहायता की है।

मंहगाई रोकने में असफलता

यूपीए का पिछला 20 महीनों का शासन असफलताओं की दुखद गाथा है। हम, गत् लगभग 20 महीनों से आवश्यक वस्तुओं के बढ़ते हुए मूल्यों के विरूद्ध अपना संघर्ष जारी रखे हुए हैं। कीमतें कम करने के बजाय यह सरकार उन वस्तुओं की सूची में वृद्धि करती जा रही है जो दिन–प्रतिदिन महंगी होती जा रही हैं। शेक्सपीयर हेमलेट में मारसेल्लुयस होरोटिओ को बताता है कि ''डेनमार्क में कहीं–न–कहीं कुछ सड़ रहा है''। इसी प्रकार यूपीए शासन काल में हमेशा कुछ–न–कुछ सड़ता रहा है। पूर्व में, उच्चतम न्यायालय की फटकार के बावजूद इस सरकार ने अनाज को सड़ने दिया और उसे भूखों में बांटने के लिए मना कर दिया। अब वे बंदरगाहों में आयातित प्याज को सड़ने दे रहे हैं जबकि आम आदमी को उचित मूल्य पर प्याज भी उपलब्ध नहीं हो पा रहा। स्वतंत्र भारत के इतिहास में यूपीए–2 सबसे मंहगा शासन काल साबित होगा।

विकसित पूर्वोत्तर के लिए हमारा विज़न

चाहे मंहगाई का मुद्दा हो या विकास का, दोनों मामलों में इस सरकार के रवैये में गंभीरता की कमी दिखती है।

पूर्वोत्तर के मामले में कांग्रेस का रवैया हमेशा ही संवेदनाविहीन रहा है। वर्षों तक, केन्द्र की कांग्रेस सरकारों के लिए उत्तर–पूर्व का क्षेत्र दुधारू गाय रहा है। भयंकर भ्रष्टाचार ने कांग्रेस के राजनीतिज्ञों को अमीर बना दिया है जबकि नागरिकों के हिस्से कुछ नहीं आया। आज असम में, वर्तमान राज्य सरकार ने प्रत्येक सरकारी विभाग को भ्रष्टाचार की उपजाऊ भूमि में तब्दील कर दिया है। इस सम्बन्ध में लगता है असम के सत्ताधीशों को दिल्ली के सत्ताधीशों से प्रेरणा मिल रही है।

मित्रों, इस क्षेत्र को राजग की सरकार बनने तक पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिये एक स्वतंत्र विभाग के गठन की प्रतीक्षा करनी पड़ी। अटल बिहारी वाजपेयीजी की सरकार के कारण ही इस क्षेत्र के विकास के लिये विशेष रूप से व्ययगत न होने वाले फंड का एक पूल बनाया गया था। परन्तु गत 6 वर्षों के दौरान इस पूल का कोई उपयोग ही नहीं किया गया है। दुर्भाग्यवश, केन्द्र में यूपीए और इस क्षेत्र में कांग्रेसनीत सरकारें अदूरदर्शिता से ग्रसित हैं। राजग ने नागालैंड में एक सफल युद्धविराम समझौते के माध्यम से एक महान अवसर प्रदान किया था। परन्तु 1997 के 14 वर्षों के बाद भी यूपीए इसे आगे बढ़ाने में असफल रहा। पूर्वोत्तर के किसी भी राज्य में चिरस्थाई शान्ति लाने और तेजी से विकासात्मक ढांचा बनाने की दिशा में बिल्कुल कोई कदम नहीं उठाया गया। लोगों के दिलों को जीतने के लिए बिना सोचे समझे किए गए उपायों से अस्थायी शांति के अलावा केन्द्र सरकार को कुछ भी हासिल नहीं हुआ है। चाहे वह नागालैण्ड हो मणिपुर हो या कोई अन्य राज्य हो, आतंकवाद के चलते भारी नुकसान हुआ है। वहां टकराव को मात्र कुछ समय के लिए

रोक देना पर्याप्त नहीं है। केन्द्र सरकार को विकास के लिए एक स्पष्ट दूरदर्शी दृष्टिकोण अपनाना होगा। प्रत्येक क्षेत्र में कनेक्टिविटी को कई गुणा बढ़ाना होगा। व्यापक स्तर पर तेजी से ढांचागत विकास की बड़ी आवश्यकता है। आर्थिक विकास के साथ–साथ भावनात्मक एकता लाना भी जरूरी है। लगातार कई दशकों से पूर्वोत्तर में हमारे भाई–बहिनों को तेजी से विकास के अवसरों से वंचित रहना पड़ा है।

मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि भाजपा एक ऐसी राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी है जिसके एजेंडा में पूर्वोत्तर सदैव प्राथमिकता पर रहा है। मुझे प्रसन्नता है कि हमारे पूर्वोत्तर संपर्क प्रकोष्ठ ने विभिन्न गतिविधियों और परियोजनाओं के साथ अपना कार्य आरंभ कर दिया है। मुझे आपको यह बताते हुये प्रसन्नता है कि हमने इस क्षेत्र के समग्र विकास के लिए कुछ विशेष प्रयास किए हैं।

1. भाजपा ने एक पूर्वोत्तर भारत 2025 दृष्टिकोण दस्तावेज तैयार करने के लिए नीति अनुसंधानकर्ताओं और विशेषज्ञों के एक दल का गठन किया है। इस परियोजना पर कार्य आरंभ हो चुका है और मैं आशा करता हूं कि हम फरवरी 2011 के अंत तक इस विज़न दस्तावेज के प्रारूप को जारी कर सकेंगे।

2. पार्टी स्तर पर हमने एक स्वतंत्र पूर्वोत्तर संपर्क प्रकोष्ठ की स्थापना की है और इसके माध्यम से हम कुछ ऐसे मेट्रो शहरों में अनौपचारिक सहायता केन्द्र तंत्र की स्थापना करेंगे, जहां पर इस क्षेत्र से आए भारी संख्या में विद्यार्थी अध्ययन कर रहे हैं।

भाजपा में यह हमारा सुविचारित मत है कि इस क्षेत्र के विकास के प्रति यूपीए और केन्द्र की पूर्व कांग्रेस की सभी सरकारों ने उचित ध्यान नहीं दिया है। सदैव तदर्थ रवैया और अल्पकालीन समाधान का सहारा लिया गया। हमारा यह मानना है कि सुशासन के माध्यम से इस क्षेत्र के विकास की तेज रफ्तार से इस क्षेत्र के लोगों और देश के अन्य भागों के लोगों के बीच और अधिक तालमेल बिठाने में सुविधा होगी और इन सभी के परिणामस्वरूप– भावनात्मक संबंध और मजबूत होंगे। इस तथ्य की पृष्ठभूमि में हमने विभिन्न राज्यों में भाजपा की सरकारों के द्वारा किए गए कुछ अत्यंत सफल विकास कार्यों और उनके द्वारा लागू की गई योजनाओं की प्रदर्शनी का आयोजन किया है। इस सुराज संकल्प प्रदर्शनी से असम के लोगों को यह पता चलेगा कि सुराज से भाजपा का क्या अर्थ है। मुझे विश्वास है कि असम के लोग और विशेषकर गुवाहाटी के लोग भारी संख्या में इस प्रदर्शनी को देखने के लिए आयेंगे।

इस के अलावा असम में रह रहे विभिन्न छः समुदायों की उन्नति से जुड़े एक विषय को भी मैं स्पर्श करना चाहूंगा, असम में रहने वाले मोरान, मोटोक, कोच–राजबोंगशी, ताई–अहोम, चाय जनजातीया तथा सुतिया इन समुदायों के विकास के विषय में भाजपा ने अपनी चिंता हमेशा जताई है। इसी सन्दर्भ में हमने इन समुदायों को अनुसूचित जनजातियों का दर्जा दिया जाने की बात बहुत पहले से की है। मैं इस अवसर पर हमारी इस मांग को दोहरा रहा हूं। भाजपा केन्द्र और राज्य सरकारों से अपील करती हैं कि वह अनुसूचित जाति दर्जा प्राप्त समुदायों की विद्यमान स्थिति को बरकरार रखते हुए इस मांग को स्वीकार करे और क्रियान्वयन की दिशा में यथा शीघ्र कदम उठाये, भाजपा अगर आगामी लोकसभा चुनावों में सफल होती है। तो वह इस मांग के अनुवर्तन के लिए सभी प्रयास करने के प्रति प्रतिबद्ध हैं।

सुराज के प्रति हमारी वचनबद्धता

इस अवसर पर, मैं भाजपा और उसके सहयोगी दलों द्वारा शासित राज्य सरकारों की महत्वपूर्ण उपलब्धियों के बारे में बताना चाहूंगा। मुझे आपको यह बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि जीडीपी सहित अनेक सामाजिक–आर्थिक संकेतकों के आधार पर भाजपा और सहयोगी दलों वाले प्रदेश अच्छा काम कर रहे हैं। मैं अपनी मध्य प्रदेश सरकार को उनके द्वारा 'लोकसेवा गारंटी अधिनियम' लागू करने के लिए बधाई देता हूं। यह एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा किसी भी सरकारी अधिकारी के समक्ष लंबित मामलों को तेजी से निपटाने में सहायता मिलेगी और किसी भी कार्य के लिए निर्धारित समय में उसे पूरा करने में भी सहायता मिलेगी। यदि कोई सरकारी कर्मचारी निर्धारित समयावधि का पालन नहीं करता तो उसे अपने वेतन से मुआवजा देना पड़ेगा। इसी प्रकार मैं हिमाचल सरकार को भी बधाई देता हूं जिसने 'इंडिया टूडे' की राज्य प्रतियोगिता में राष्ट्रीय स्तर पर चार पदक जीते हैं। 'फास्टर मूवर कैटेगरी' में भी राजग के सभी राज्यों ने पांच पुरस्कार जीते हैं। कृषि विकास में गुजरात की तेज गति की सभी ओर से प्रशंसा की गई है और मैं इसके लिए अपनी सरकार को बधाई देता हूं। मैं छत्तीसगढ़ सरकार को तेजी से आर्थिक विकास के लिए और शिक्षा विकास और निवेश के मामलों में क्रमशः झारखंड, बिहार और उत्तराखंड सरकार को भी बधाई देता हूं। कर्नाटक ने भी सुचारू यातायात प्रणाली के लिए कुछ प्रतिष्ठित पुरस्कार अर्जित किए हैं।

पिछले वर्ष में हमने विकासोन्मुखी सुशासन के लिए काम करने की जरूरत पर बल दिया है। अनेक गतिविधियों के माध्यम से हमने विकास के लिए राजनीति की हमारी

अवधारणा को और गतिशील बनाया है।

अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य

बंधुओं, भारत के विदेशी मामलों से संबंधित कुछ प्रमुख मुद्दों के संबंध में मैं कुछ सामान्य आकलन पर बात करना चाहता हूं। भारत–अमरीका संबंध, शीत युद्ध की समाप्ति के बाद से और 21वीं शताब्दी के प्रारंभिक दशक के दौरान भारत के लिए अधिक महत्वपूर्ण रहे हैं। भाजपा इन संबंधों के उत्तरोत्तर मजबूती के प्रति दृढ़ता से वचनबद्ध है और अपने शासनकाल के दौरान इन महत्वपूर्ण संबंधों को और अधिक बढ़ाने में उसके द्वारा किए गए योगदान पर भारी गर्व महसूस करती है। तथापि 1998 –2004 के दौरान बनाए गए महत्वपूर्ण संबंध के मानदंड कतिपय मामलों में समाप्त होते प्रतीत हुए हैं। हमारे पारस्परिक संबंधों के बीच इस प्रकार से परिवर्तन लाया गया है जिसका उद्देश्य कतिपय मामलों में भारत की सुरक्षा और आर्थिक हितों और इससे भी महत्वपूर्ण पाकिस्तान समर्थित सीमापार आतंकवाद के विषय का कम आंकना है। यूपीए सरकार की कूटनीतिक विफलता कि यह अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को पाकिस्तान द्वारा आतंकवाद को बढ़ावा देने से रोकने के लिए मनाने और इसके इस दावे कि वह स्वयं भी आतंकवाद का शिकार है, को रोकने के मामले में विनाशकारी ही सिद्ध हुई है। भाजपा आशा करती है कि सरकार अमरीकी राष्ट्रपति ओबामा की हाल की भारत यात्रा का लाभ उठाने हेतु विशेष रूप से आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई के संबंध में, आवश्यक कदम उठाएगी।

अन्त्योदय के मोर्चे पर भी हमें एक ऐसा वातावरण तैयार करना होगा जहां पर सेवा, शिक्षा, संस्कार और विकास के लिए परियोजनाएं आरंभ करना एक आम बात बन जाए। महात्मा गांधी राजनीति को अध्यात्मोन्मुखी बनाना चाहते थे। अध्यात्मिकता एक बहुत बड़ी बात है। परंतु इसमें पहले हमें समाज के वंचित वर्गों की कठिनाईयों से पार्टी कार्यकर्ताओं को अवगत कराना है और उन्हें इन वर्गों के लिए काम करने के लिए प्रेरित करना है। अन्त्योदय कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य यही है।

यूपीए की पाकिस्तान नीति

यूपीए–2 के गत् 20 महीनों के दौरान हम वास्तव में अपनी पाकिस्तान संबंधी नीति के बारे में अत्यधिक आघातपूर्ण, भौंडा एवं भारी दुखदायीपूर्ण रवैया देखते आ रहे हैं। यह सभी 2009 में शरम–अल–शेख में की गई अवर्णनीय गलती से आरंभ हुआ है (भारत–पाक संयुक्त वक्तव्य में बलूचिस्तान में भारत की कथित और काल्पनिक और अव्यवस्था फैलाने वाली भूमिका को शामिल करने की अनुमति देना)। इसके बाद हमारे विदेश मंत्री को उनके पाकिस्तानी समकक्ष द्वारा वर्ष 2010 में सार्वजनिक रूप से धमकाने और झिड़की देने का मामला सामने आया। केन्द्रीय गृहमंत्री द्वारा कई प्रकार की जानकारी रखने वाले दस्तावेज को पाकिस्तानी प्राधिकारियों द्वारा कार्रवाई करने योग्य न समझा जाना और उसे मात्र साहित्य करार देना, सबसे ताजा झिड़की का सबूत है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि हमने यह देखा है कि हम पर यह बदनामी जबर्दस्ती थोपी गई है। क्योंकि हमने अपने लक्ष्यों के सिद्धांतों को छोड़ दिया है। पहले हमने वार्ता से पहले पाकिस्तान द्वारा ठोस कार्रवाई करने पर जोर दिया था। तथापि बाद में एक समय हमने अपनी नीति में परिवर्तन किया और इस बात पर सहमत हो गये कि वार्ता अनिवार्य है और इसे आरंभ किया जाना चाहिए बगैर इसकी परवाह किए कि पाकिस्तान को कोई कार्यवाही करनी चाहिए।

यह हमारी रणनीतिक पहल के अभाव का नतीजा है कि हमारे द्वारा आवश्यक प्रभावी कदम न उठाए जाने के कारण भारत–पाकिस्तान विवाद के बारे में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का पुराना रवैया बरकरार है।

भारत-चीन संबंध :

चीन गणराज्य के साथ सहयोगी संबंधों को आगे बढ़ने के लुभावने तर्क से इंकार नहीं किया जा सकता और भाजपा को इस प्रकार के व्यापक प्रगतिशील संबंधों के प्रति कोई संदेह नहीं है। इस तथ्य से इंकार नहीं किया जा सकता कि अपनी सक्रिय कूटनीति के माध्यम से राजग सरकार ने यह सुनिश्चित किया कि चीन गणराज्य के साथ संबंध और अधिक इतने सुदृढ़ बने कि चीन ने जून 2003 में अटलजी की चीन की ऐतिहासिक यात्रा के दौरान सिक्किम को भारतीय संघ का एक प्रभुसत्ता सम्पन्न अभिन्न अंग औपचारिक रूप से माना। हम सभी चीन के साथ मैत्रीपूर्ण और परस्पर लाभदायी संबंधों के पक्ष में हैं। हम आशा करते हैं कि सरकार चीन गणराज्य के साथ अपने संबंधों में अपने हितों को ध्यान में रखकर एक दूरदर्शी रवैया अपनाएगी जिसके अन्तर्गत पारस्परिक लाभदायक और द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ाने के मामले में सहयोगात्मक संबंधी ठोस कार्य किए जाएंगे।

श्रीलंका

लिट्टे की पराजय के बाद से श्रीलंका निर्माण और पुनर्वसन के पथ पर है। तमिल लोग अभी भी गांवों में पूर्ण पुनर्वसन और पूरी तरह से अन्यों से जुड़ने की प्रतीक्षा में हैं। बच्चों और महिलाओं को पर्याप्त स्वास्थ्य देखभाल तथा

सामान्य रूप से नागरिकों को उनके आत्म–सम्मान तथा प्रतिष्ठा के साथ मुख्यधारा में लाए जाने की जरूरत है।

वर्ष २०१० की समीक्षा

मित्रों, हम इस नए वर्ष में यहां पर हैं और इस नए वर्ष में प्रवेश करते समय हमें गत् वर्ष की समीक्षा करनी चाहिए। हम सभी को प्रसन्नता होगी कि पिछले वर्ष श्री रामजन्मभूमि के बारे में हमें न्यायालय का ऐतिहासिक निर्णय सुनने को मिला। हमने पहले ही इसका स्वागत किया है और हम आशा करते हैं कि समाज के सभी वर्ग अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनाने में सहायता करेंगे।

पिछला वर्ष समूचे देश में तेजी से हुई पार्टी गतिविधियों से परिपूर्ण रहा। हमने प्रशिक्षण जैसे कुछ विभागों को और सुदृढ़ बनाया है। हमारे तीन स्तरीय कार्यकर्ता प्रशिक्षण कार्यक्रम को बहुत अच्छा प्रत्युत्तर मिला है। 15000 से अधिक पार्टी कार्यकर्ताओं ने अब तक हमारे प्राथमिक स्तर के क्षमता निर्माण कार्यक्रम में भाग लिया है तथापि हमें अभी भी अपनी प्रशिक्षण गतिविधियों को और अधिक सुचारू और परिणान्मोमुखी बनाना है। हमें एक ऐसा वातावरण तैयार करना है जिसमें प्रशिक्षण के माध्यम से हम जिन मूल्यों का समावेश करते हैं वह और अधिक स्पष्ट हो सकें। यदि ऐसा किया जाता है तो प्रशिक्षित और अप्रशिक्षित के बीच अंतर और अधिक स्पष्ट हो जाएगा। इसी प्रकार अन्त्योदय के मोर्चे पर भी हमें एक ऐसा वातावरण तैयार करना होगा जहां पर सेवा, शिक्षा, संस्कार और विकास के लिए परियोजनाएं आरंभ करना एक आम बात बन जाए। महात्मा गांधी राजनीति को अध्यात्मोन्मुखी बनाना चाहते थे। अध्यात्मिकता एक बहुत बड़ी बात है। परंतु इसमें पहले हमें समाज के वंचित वर्गों की कठिनाईयों से पार्टी कार्यकर्ताओं को अवगत कराना है और उन्हें इन वर्गों के लिए काम करने के लिए प्रेरित करना है। अन्त्योदय कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य यही है। मुझे यह बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि अब हम असंगठित कामगार महासंघ नामक संगठन के माध्यम से असंगठित कामगारों तक पहुंचने के लिए कुछ ठोस प्रयास कर सकते हैं। मैं आप सभी से अपेक्षा करता हूं कि आप इस नए प्रयास में गहरी रूचि दिखाएं और इस नए संगठन के माध्यम से असंगठित क्षेत्र के कामगारों तक पहुंचें।

मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि अब हमने अनेक नए प्रकोष्ठ भी बनाए हैं जिनका प्रमुख उद्देश्य विभिन्न क्षेत्रों में रूचि रखने वाले लोगों को शामिल करना है। राजनीतिक पार्टियों को सक्रियता का वाहक होना होगा। मुझे विश्वास है कि हमारे नए प्रकोष्ठ उन सभी के लिए उपयुक्त साधन साबित होंगे जिनके पास अनुभव, विशेषज्ञता और जोश तो है, परंतु उनके पास अपने स्वयं की सक्रियता का उपयोग करने के लिए कोई संगठनात्मक साधन नहीं है। जिन अनेक नए प्रकोष्ठों का हमने गठन किया है उनमें से सुराज प्रकोष्ठ, सांसद–पूर्वोत्तर संपर्क प्रकोष्ठ और सांसद–विधायक विकास प्रकोष्ठ ने अपना कार्य पूरी सक्रियता से प्रारम्भ कर दिया है। जैव–ऊर्जा प्रकोष्ठ, मानवाधिकार प्रकोष्ठ जैसे प्रकोष्ठों ने भी अपनी गतिविधियां प्रारम्भ कर दी हैं। परंतु उन्हें अभी बहुत कुछ और करना है। मुझे आशा है कि नए अथवा पुराने प्रकोष्ठ भी पूर्ण सक्रियता से अपना कार्य आरम्भ करेंगे और उनके द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करेंगे। मैं सभी प्रकोष्ठों के संयोजकों को गत् कुछ महीनों की उनकी गतिविधियों से संबंधित रिपोर्ट तैयार करने और उसे मुझे भेजने के लिए आग्रह कर रहा हूं। वास्तव में, भाजपा में हमने सदैव ''रिपोर्ट तैयार और प्रस्तुत करने'' को एक अच्छी परम्परा माना है और हम सभी को उसे अपनाने का प्रयास करना चाहिए। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि मैंने स्वयं भी एक रिपोर्ट तैयार की है और वह शीघ्र ही आपके पास पहुंच जाएगी।

मुझे यह घोषणा करते हुए अत्यन्त प्रसन्नता हो रही है कि पार्टी के नए मुख्यालय की योजना को अंतिम रूप दिया जा चुका है। इसमें न केवल हमारा केन्द्रीय कार्यालय रहेगा अपितु एक अनुसंधान विभाग और एक प्रशिक्षण विभाग भी वहां से चलेगा। हम सत्ता की स्वाभाविक पार्टी हैं और इसलिए हमें शासन के वैकल्पिक ढांचों पर काम करना चाहिए। इस संदर्भ में हम एक भाजपा अनुसंधान विभाग स्थापित कर रहे हैं जो नीति विशेषज्ञों और अनुसंधान के विभिन्न क्षेत्रों के पेशेवरों से मिलकर नीतिगत अनुशंसाएं देगा। विभाग हमारी राज्य सरकारों के 'सर्वोत्तम नवोन्मेषी कार्यों' का अध्ययन और प्रदर्शन भी करेगा। हम विभिन्न राज्यों में भी अपने वरिष्ठ नेताओं जैसे जगन्नाथ राव जोशी (कर्नाटक) और सुंदर सिंह भण्डारी (राजस्थान) की स्मृति में अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान स्थापित करने की संभावनाओं पर विचार कर रहे हैं।

बंधुओं, आने वाला वर्ष चुनौतियों से भरा हुआ है। गुवाहाटी छोड़ने से पहले हमें असम के लोगों से यह वादा लेना होगा कि वह इस राज्य में ऐसी पहली सरकार बनाएं जिसके शपथ ग्रहण समारोह के लिए हमें दोबारा यहां आना पड़े। अपनी ओर से भी हमें इसके लिए हमें कड़े प्रयास करने होंगे। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी के चुनावों से हमें अपना समर्थन आधार के विस्तार करने का अवसर मिलेगा। हमें समर्थन आधार का विकास करने और समाज के नए वर्गों में अपना स्थान बनाने के लिए सदैव प्रयास करना होगा।

भारतीय राजनीति में निर्णायक बदलाव का वक्त : आडवाणी

गुवाहाटी (असम) में संपन्न भारतीय जनता पार्टी की दो दिवसीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक के अंतिम दिन अपने समापन सम्बोधन में भाजपा संसदीय दल के अध्यक्ष श्री लालकृष्ण आडवाणी ने 2010 को 'बहुत ज्यादा घोटालों' का वर्ष बताया और कहा कि भारतीय राजनीति में निर्णायक बदलाव का वक्त आ गया है। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हम भ्रष्टाचार व घोटालों के मुद्दों पर 2014 के चुनाव में जाएं और उसे जीतना लक्ष्य बनाएं। श्री आडवाणी ने कहा कि हमारे समक्ष सबसे बड़ी चुनौती अपनी छवि साफ–सुथरी रखने की है ताकि हम जनता के बीच उनका समर्थन मांगने जाएं तो कोई हम पर ऊंगली ने उठाए। श्री आडवाणी ने बोफोर्स कांड के मसले पर कहा कि आम लोग यही समझते हैं कि सरकार ने बोफोर्स कांड को दबा दिया। यहां तक कि इनकम टैक्स विभाग ने भी कह दिया है कि क्वात्रोकी ने बोफोर्स कांड में कमीशन लिया। फिर भी सीबीआई ने इस मामले को खत्म करने की बात कही है। उन्होंने कहा कि इसकी वजह से भारत की छवि धूमिल हुई है। उन्होंने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से अपील की कि वे या तो इस मामले में विरोध प्रकट करें या फिर आगे जांच के आदेश दें।

हम राष्ट्रीय स्तर पर दो सम्मेलन भी आयोजित करने जा रहे हैं। इस एक सम्मेलन में न्यायिक सुधारों के बारे में चर्चा की जाएगी। पिछले दिनों न्यायपालिका में घटित घटनाक्रमों पर हम चिंतित हैं। न्याय प्रदान करने की प्रकिया को और तेज बनाने के लिए नवोन्मेषी उपायों पर विचार करना अत्यन्त आवश्यक है। यदि प्रबल व्यवस्थागत सुधार नहीं किया गया तो लोगों का न्यायपालिका से भरोसा उठ जाएगा। दूसरा सम्मेलन जिसकी हम योजना बना रहे हैं हमारे उन कार्यकर्त्ताओं का होगा जो किसी सहकारी संस्था से सक्रिय रूप से जुड़े हुए हैं। अधिवक्ता प्रकोष्ठ और सहकारिता प्रकोष्ठ इन सम्मेलनों की योजना बना रहे हैं। मुझे यह भी घोषणा करनी है कि पार्टी ने हमारे सम्मानित नेता माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी द्वारा दिए गए भाषणों और लिखे गए सभी लेखों का संकलन 'समग्र अटल जी' नामक परियोजना के अन्तर्गत करने का निर्णय लिया है। इस परियोजना का 1 वर्ष की अवधि के दौरान विस्तृत ब्यौरा तैयार किया जाएगा और आपको इस बारे में शीघ्र ही जानकारी मिल जाएगी। रामभाऊ म्हाळगी प्रबोधिनी, मुंबई इस परियोजना को क्रियान्वित करेगी।

आओ, हम आशा को पुनर्जाग्रत करें

मित्रों, हम अपने देश के इतिहास के एक निर्धारक मौके पर गुवाहाटी में एकत्रित हुए हैं। समूचे देश में लोग यूपीए–2 के कामकाज अथवा इसके अभाव से पूरी तरह निराश हैं। कभी कांग्रेस ने एक ऐसी सरकार देने का वादा किया था जो काम करेगी। लेकिन आज यूपीए ने हमें एक ऐसी सरकार दी है जो काम करना तो दूर, अपने दायित्व से ही जी चुरा रही है। मनमोहन सिंह सरकार ने भ्रष्टाचार में लिप्त होने तथा साथ–साथ विभिन्न किस्म के घपलों और घोटालों में शामिल होने के मामले में अब तक के सारे रिकार्ड तोड़ दिए हैं। जनता के धन की लूट केवल दिल्ली तक सीमित नहीं है। यहां असम में भी एक ऐसी सरकार है जिसके खाते में अनेकों घोटाले दर्ज हैं। हमें इन प्रवृत्तियों के विरूद्ध लड़ना है और लोगों को बोफोर्स, कॉमनवेल्थ खेलों, आदर्श सोसायटी तथा स्पेक्ट्रम घोटाले की सच्चाई के बारे में जाग्रत करना है।

दूसरी तरफ, हम पर भ्रष्टाचार, भूख और आतंक से मुक्त राष्ट्र बनाने की जिम्मेदारी है। डॉ॰ श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पं॰ दीनदयाल उपाध्याय के जीवन से प्रेरणा लेकर हमें राष्ट्रीय पुनर्निर्माण हेतु एकजुट होकर काम करना है। लोग भाजपा और राजग की ओर भारी आशाओं से देख रहे हैं। हमें इन लोगों के दिलों में आशा पुनर्जाग्रत करने का दायित्व निभाना है, जो हरेक को स्वार्थी समझ रहे हैं। इस समय हम मार्गदर्शन के लिए अपने सभी शीर्ष नेताओं की ओर देख रहे हैं। ब्रह्मपुत्र के तट पर आपके बीच खड़े होकर मैं अपने महान नेता अटल बिहारी वाजपेयी की भविष्यवाणी को याद किए बिना नहीं रह सकता। तीस वर्ष पहले मुंबई में अरेबियन समुद्र के तट पर खड़े होकर उन्होंने अंधेरा दूर करने, प्रकाश लाने और कमल खिलाने का वादा किया था। मैं अपने प्रेरणादायी नेता के शब्दों को दोहराता हूं और दावा करता हूं : vèkjk NVxk] lj t fudyxk] dey f[kyxkA

जय भारत, धन्यवाद। ■

कांग्रेस की वोट-बैंक की राजनीति के चलते घुसपैठ बढ़ी

गुवाहाटी (असम) में भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक में भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री श्री रविशंकर प्रसाद ने ''असम और पूर्वोत्तर की संवेदनशील स्थिति'' पर प्रस्ताव प्रस्तुत किया, जिसका अनुमोदन भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्रीमती विजया चक्रवर्ती ने किया। यह प्रस्ताव सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया। हम इस प्रस्ताव का पूरा पाठ यहां प्रकाशित कर रहे हैं:–

Vसम और पूर्वोत्तर के अन्य राज्यों की एक विचित्र भूराजनीतिक स्थिति है क्योंकि यह पांच देशों, भूटान, नेपाल, चीन, म्यांमार और बंगलादेश से घिरा हुआ है। समूचे पूर्वोत्तर की भूमि बहुत ही सुन्दर, विविधतापूर्ण और अत्यधिक क्षमता वाली है। यह हमारी समृद्ध और विविधतापूर्ण संस्कृति और सभ्यता की विरासत के कुछ शानदार पहलुओं को दर्शाती है। पूर्वोत्तर के लोग, जो गौरवशाली भारतीय हैं, इस समृद्ध विरासत के प्रतिरूप हैं। तथापि, यह बड़े दुःख और दुर्भाग्य की बात है कि आज समूचा पूर्वोत्तर कई प्रकार के भ्रष्टाचार, उग्रवाद, आतंकवाद, कुप्रशासन और सीमा पार से घुसपैठ जैसी अनेक समस्याओं से पीड़ित है। कांग्रेस, जो पूर्वोत्तर के अधिकांश राज्यों में सत्ता में है, की वोट बैंक की राजनीति इन्हें और पोषित करती है। इससे भी बड़ी दुर्भाग्य की बात यह है कि भारत के प्रधानमंत्री, डॉ0 मनमोहन सिंह पूर्वोत्तर से राज्य सभा के सांसद हैं और असम का प्रतिनिधित्व करते हैं। भाजपा ने बहुत सोच समझकर पूर्वोत्तर की चिंताजनक स्थिति के संबंध में एक विशेष प्रस्ताव पारित करने का निर्णय लिया है जिसका उद्देश्य न केवल इसकी समस्याओं की ओर ध्यान आकर्षित करना है अपितु अपनी इस प्रतिज्ञा को दोहराना भी है कि वह असम और पूर्वोत्तर के लोगों के साथ है और उनकी बेहतरी के लिये हर संभव प्रयास करेगी।

बंगलादेश से घुसपैठ

असम, पूर्वोत्तर के विभिन्न भागों और दिल्ली सहित भारत के अनेक अन्य भागों में बंगलादेश से भारी घुसपैठ आज भारी चिंता का विषय है। वास्तव में, विशेष रूप से असम में प्रवासियों की संख्या बहुत ही चिंताजनक स्थिति में पहुंच गई है। जनगणना के आंकड़े इस खतरनाक प्रवृत्ति का प्रमाण है। वर्ष 1991 में असम में 1.18 करोड़ मतदाता थे। यह संख्या बढ़कर वर्ष 2001 में 1.44 करोड़ और वर्ष 2010 में 1.79 करोड़ हो गई। इस तरह दो दशकों में इसमें 61 लाख की वृद्धि हुईं। राज्य में 126 विधान सभा क्षेत्रों में से 82 क्षेत्रों में 2004 (लोकसभा चुनाव) और 2006 (विधान सभा चुनाव) के बीच की अवधि में मतदाताओं की संख्या में प्रतिवर्ष 7 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हुई। इसकी तुलना में 1999 और 2004 की अवधि में अखिल भारतीय मतदाताओं की संख्या में प्रतिवर्ष 1.67 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी। इन 82 विधानसभा क्षेत्रों में से 18 क्षेत्रों में प्रतिवर्ष 10 प्रतिशत से भी अधिक वृद्धि हुई जिसमें धेकियाजुली में सबसे अधिक प्रतिवर्ष 22. 5 प्रतिशत की वृद्धि हुई। इतनी भारी मात्रा में घुसपैठ न केवल आबादी का स्वरूप ही बदल रही है, अपितु इससे देश की शासन प्रणाली पर भी भारी कुप्रभाव पड़ रहा है। यदि इस प्रकार की खतरनाक स्थिति पर नियंत्रण नहीं लगाया जाता, तो कौन जानता है कि निकट भविष्य में एक घुसपैठिया असम का मुख्यमंत्री न बन जाये जिसकी पूरी आशंका है।

इस संबंध में पूरे प्रमाण मौजूद हैं जिनसे यह पता चलता है कि कांग्रेस पार्टी ने अनेक जिम्मेदार पक्षों द्वारा बार–बार दी गई चेतावनी के बावजूद इस खतरे के प्रति आंखें मूंद रखी हैं और यहां तक कि उसने इस संबंध में उच्चत्तम न्यायालय के निर्देशों को भी अनदेखा किया है। वास्तव में, आईएमडीटी अधिनियम (न्यायाधिकरणों द्वारा अवैध प्रवासी निर्धारण अधिनियम) 1983 कांग्रेस सरकार द्वारा लाया गया था जिसके द्वारा उन नागरिकों, जो असम के

निवासी हैं, के लिये विदेशी/अवैध प्रवासियों की पहचान करना और उन्हें वापस भेजना असंभव बना दिया था। यह अधिनियम, जिसे घुसपैठियों की पहचान करने और उन्हें वापस भेजने के स्पष्ट उद्देश्य से बनाया गया था, वास्तव में असम में उनके स्थायी निवास का एक माध्यम बन गया। समूचे देश में लागू विदेशी अधिनियम, 1946 के अधीन अवैध प्रवासियों का यह दायित्व है कि वे यह सिद्ध करें कि वे भारतीय नागरिक हैं जबकि आईएमडीटी के अधीन शिकायतकर्ता का यह दायित्व है कि वे सिद्ध करें कि फलां आदमी विदेशी है। इस भेदभावपूर्ण कानून, जो घुसपैठियों की पहचान करने और उन्हें वापस भेजने हेतु पूर्णतया निष्प्रभावी रहा, को उच्चत्तम न्यायालय में चुनौती दी गई। सुनवाई के दौरान, जब राजग सत्ता में था, तो उसने यह स्पष्ट रवैया अपनाया कि आईएमडीटी अधिनियम को केवल असम राज्य पर लागू करना स्पष्ट रूप से भेदभावपूर्ण है और सरकार इसे निरस्त करने जा रही है। जब मई 2004 में राजग सत्ता में नहीं रहा, तो कांग्रेस के नेतृत्व वाली संप्रग सरकार ने यह बताते हुए उच्चत्तम न्यायालय में एक और एफिडेविट फाइल किया कि केन्द्र सरकार ने मामले पर पुनर्विचार किया है और आईएमडीटी अधिनियम को बरकरार रखने का निर्णय लिया है जो असम राज्य पर इसी रूप में लागू होगा। इससे कांग्रेस के स्पष्ट आशय का पता चलता है कि वह घुसपैठियों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं करना चाहती।

उच्चत्तम न्यायालय ने ऐतिहासिक पृष्ठभूमि तथा भारी घुसपैठ को खतरनाक परिणामों के बारे में असम के तत्कालीन राज्यपाल की रिपोर्ट सहित मामले की विस्तृत जांच की और यह निर्णय लिया कि निस्सन्देह असम राज्य बंगलादेशी नागरिकों की भारी संख्या में घुसपैठ के कारण बाहरी आक्रमण और आन्तरिक अशांति झेल रहा है और भारतीय संघ का यह दायित्व है कि वह असम राज्य की रक्षा के लिये सभी उपाय करे, क्योंकि इससे पूर्वोत्तर क्षेत्र की अखंडता और सुरक्षा के प्रति खतरा पैदा हो रहा है। तदनुसार, उच्चतम न्यायालय ने 22 जुलाई, 2005 के अपने निर्णय में आईएमडीटी को असंवैधानिक घोषित कर दिया और यह निर्देश दिया कि अवैध प्रवासियों संबंधी सभी मामले अब विदेशी अधिनियम के उपबंधों तथा विदेशी (न्यायाधिकरण) आदेश 1964 में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार निर्णीत किये जायेंगे।

यह वास्तव में दुःख की बात है कि उक्त निर्णय का पालन करने के बजाय कांग्रेस के नेतृत्व वाली संप्रग सरकार ने उक्त निर्णय में दिये गये निर्देशों को निरस्त करने की मांग की। इसने विदेशी (न्यायाधिकरण) आदेश, 1964 में संशोधन किया और 2006 की एक अधिसूचना द्वारा यह निर्णय लिया कि विदेशी अधिनियम असम राज्य पर लागू नहीं होगा। इसका अर्थ यह हुआ कि अवैध प्रवासियों के विरूद्ध कोई कार्यवाही नहीं की जा सकी। उच्चत्तम न्यायालय पुनः चुनौती के दूसरे दौर में 5 दिसम्बर, 2006 के अपने निर्णय में यह बताया कि "2006 के आदेश द्वारा किया गया संशोधन इस न्यायालय के पूर्व निर्देशों को मात्र लागू न करने के लिये जारी किया गया है।" न्यायालय ने यह भी टिप्पणी की कि हम को एक बार फिर दुख से यह कहना है कि अवैध प्रवासियों का देश से बाहर भेजा जाना सुनिश्चित करने हेतु इच्छाशक्ति की कमी है।" न्यायालय ने 2006 के आदेश को रद्द कर दिया और संघ और राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वे विदेशी अधिनियम के अन्तर्गत अवैध प्रवासियों की पहचान करने और उन्हें वापस भेजने संबंधी न्यायालय के पूर्व निर्देशों को तुरन्त लागू करें।

Hkktik dk ;g vkjki g fd ,dek= okV cd dh jktuhfr d fy; orleku dUn ljdkj dh N=Nk;k e vle dh dkxl ljdkj dk ?kliB dk c<kok nu dk dk;l dj jgh gA lrr ?kliB d dkj.k vle d ey ykxk dk viuh Hkfe dk [kkuk iM jgk g tcfd voèk cxykn'kh lrjk Hkfe] ou Hkfe] pkjkxkg Hkfe vkj ;gk rd fd vkfnoklh Hkfe dk Hkkjh ieku ij gfFk;ku dh uhfr viuk jg gA चार भूमि, जो नदी की धारा के बदल जाने से रेत द्वीप के रूप में बदल गई है, पर भी राज्य सरकार द्वारा अवैध प्रवासियों के परिवारों को उन्हें पट्टा देकर वहां बसाया गया है। ये अवैध प्रवासी आतंक, उग्रवाद और अलगाववाद फैलाने में योगदान कर रहे हैं, तथा उसे भड़का रहे हैं, जिससे भारत की सुरक्षा और अखंडता के प्रति गंभीर खतरा पैदा हो रहा है। वे असम, पूर्वोत्तर और देश के अन्य भागों, जहां जहां वे जा रहे हैं, के मूल नागरिकों के रोजगार के अवसर भी भारी पैमाने पर हड़प रहे हैं।

भाजपा इस मामले में बहुत ही स्पष्ट है कि वे सभी मूल और देशी मुस्लिम, जो पीढ़ियों से असम में पैदा हुए हैं तथा पले–बढ़े हैं, घुसपैठिये नहीं हैं और वे एक भारतीय नागरिक को मिलने वाले सभी प्रकार के सम्मान और अधिकारों के पात्र हैं। इसके साथ–साथ यह बात भी पूरी तरह से स्पष्ट की जाती है कि हिन्दू, जिन्हें बंगलादेश में प्रताड़ना और भेदभाव के कारण भारत आने पर मजबूर होना पड़ा है, को घुसपैठिया नहीं कहा जा सकता। वे वास्तव में विस्थापित हैं जो भारत में शरण पाने के हकदार हैं। उन्हें भारत में नागरिकों के अधिकार अवश्य ही दिये जाने चाहिए और उन्हें यहां बसाया जाना चाहिए जो कि सरकारों का दायित्व है।

भाजपा राष्ट्रीय कार्यकारिणी निम्न मांगे करती हैः–

1. उच्चत्तम न्यायालय के बार–बार के निर्देशों के अनुसार विदेशी अधिनियम के उपबंधों के अन्तर्गत सभी अवैध प्रवासियों की एक निर्धारित समय अवधि में पहचान करने और उन्हें वापस भेजने के लिये तुरन्त कदम उठाये जाएं।
2. निर्वाचन आयोग द्वारा मतदान सूची में से अवैध प्रवासियों के नामों को हटाया जाना सुनिश्चित किया जाना चाहिये जैसा कि भाजपा द्वारा हाल ही में दिये गये एक ज्ञापन में मांग की गई है। संविधान के अनुसार केवल नागरिक ही मतदान कर सकते हैं और उच्चत्तम न्यायालय के निर्देश निर्वाचन आयोग के लिये समान रूप से मान्य हैं।
3. पूर्वोत्तर में बंगलादेश सहित विभिन्न देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर उचित बाड़ (फैंसिंग) होनी चाहिये। पश्चिमी सीमा पर इस प्रकार की बाढ़ लगाई गई है। दोनों देशों के बीच से गुजरने वाली नदी के आखिरी सिरे पर उचित सुरक्षा निगरानी की व्यवस्था होनी चाहिये।
4. भारी पैमाने पर घुसपैठ के कारण असम और पूर्वोत्तर में संवेदनशील और नाजुक स्थिति को ध्यान में रखते हुए नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 14–क के अनुसार प्रत्येक नागरिक का अनिवार्य पंजीकरण करने, राष्ट्रीय पहचान–पत्र जारी करने और नागरिकों का राष्ट्रीय रजिस्टर रखने के लिये उन क्षेत्रों में प्राथमिकता के आधार पर आवश्यक कार्य किया जाना चाहिये।

कांग्रेस शासन में पूर्वोत्तर में व्याप्त भ्रष्टाचार

लगभग समूचे पूर्वोत्तर, जहां पर अधिकांश राज्यों में कांग्रेस अथवा कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकारें हैं, में आज भारी पैमाने पर भ्रष्टाचार व्याप्त है, स्पष्ट रूप से राजनीतिक संरक्षण से सरकारी धन को लूटा जा रहा है और सुविधाओं से वंचित गरीब और गरीबी रेखा से नीचे के लोगों के लिए उपलब्ध सुविधाओं को भारी पैमाने पर हथियाया जा रहा है। सरकार के मंत्रियों, नौकरशाहों, ठेकेदारों और सप्लाईकर्ताओं सहित राजनेताओं की आपसी सांठगांठ से भारत सरकार से मिलने वाले अनुदान सहित सरकारी धन को व्यवस्थित तरीके से लूटा जा रहा है। भ्रष्टाचार और विकास फंड को लूटने को लेकर सत्ताधारियों और आतंकवादियों के बीच एक व्यापक अंतर्सम्बन्ध है। भाजपा एक विस्तृत पुस्तिका प्रकाशित करेगी जिसमें भारी पैमाने पर हो रही इस लूट का पर्दाफाश किया जायेगा। पार्टी इस संबंध में भारत के माननीय राष्ट्रपति को भी एक ज्ञापन देने की बात सोच रही है। तथापि, इस प्रकार के भ्रष्टाचार के कुछ उदाहरणों का नीचे उल्लेख किया जा रहा है जिनसे इन घोटालों की व्यापकता का पता चलता है जिनसे काफी चिंताजनक स्थिति पैदा हो गई हैः

- असम में एन सी हिल घोटाले, परिवहन राज सहायता के दुरूपयोग, सिंचाई घोटाले ने असम को बर्बाद कर दिया है। राष्ट्रीय जांच एजेसी (एन आई ए) ने उत्तर कछार पर्वतीय स्वायत्तशासी जिला परिषद में लगभग 100 करोड़ रूपए के घोटाले का पता लगाया। एन आई ए ने यह पता लगाया कि बहुत से मंत्री और अनेक नौकरशाह इस घोटाले से लाभान्वित हुए हैं। सी बी आई ने घोटालेबाजों के घर से 13.45 करोड़ रूपए की भारी नकद धनराशि बरामद की थी।
- असम में लगभग एक करोड़ लोगों की पहचान गरीबी रेखा से नीचे के रूप में की गई। यह आरोप लगाया गया है कि गरीबी रेखा से नीचे परिवारों के लिए आवंटित चावल का लगभग 50 प्रतिशत भाग, जिसका मूल्य 1000 करोड़ बैठताा है, काला बाजार में चला जाता है। असम में सार्वजनिक वितरण प्रणाली में भारी लीकेज है, भ्रष्टाचार व्याप्त है और हेराफेरी होती है।
- अरूणाचल प्रदेश में देश का सबसे बड़ा सार्वजनिक वितरण प्रणाली घोटाला हुआ जिसमें सत्तारूढ़ पार्टी के लगभग 100 नेताओं और अधिकारियों सहित पूर्व कांग्रेसी मुख्यमंत्री गेगांग अपांग राशन/सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अनाज की काला बाजारी करने में शामिल पाये गये। 1000 करोड़ रुपए के इस घोटाले में गुवाहाटी उच्च न्यायालय द्वारा गठित विशेष जांच प्रकोष्ठ द्वारा पूर्व मुख्यमंत्री गिरफ्तार किये गये थे।
- मणिपुर में लोटक झील की सफाई के नाम पर 244 करोड़ रुपए की भारी लूट का मामला सामने आया। भारत सरकार द्वारा प्रायोजित तथा वित्त पोषित झील की सफाई संबंधी इस परियोजना की सारी धनराशि व्यर्थ जा रही है। जिस फर्म को यह ठेका दिया गया था वह नकली पाई गई और वह मणिपुर के मुख्यमंत्री के तथाकथित कुछ संबंधियों के साथ जुड़ी हुई थी।
- अरूणाचल प्रदेश का एस.जी.आर.वाई. घोटाला ओर पनबिजली आवंटन घोटाला भी लगभग बदनाम 2–जी स्पैक्ट्रम घोटाले की तरह ही है।
- जवाहरलाल नेहरू अर्बन रिन्यूअल मिशन के अन्तर्गत परियोजना के क्रियान्वयन, खाद्य नियंत्रण और वितरण, पीने के पानी, बांधों का निर्माण और भर्ती में भी घोटाले हुए।
- खानों (माइनिंग) का आवंटन उत्तर पूर्व में भ्रष्टाचार का एक प्रमुख स्रोत बन चुका है।

भाजपा गरीब और जरूरतमंद लोगों के लिये निर्धारित सरकारी धन की लूट के इस आप्रेशन के विरूद्ध बड़े पैमाने पर एक अभियान आरंभ करने के लिये वचनबद्ध हैं। भारी पैमाने पर हो रहे भ्रष्टाचार से पूर्वोत्तर राज्यों में गरीबी और पिछड़ापन बढ़ा है। सी ए जी, मीडिया और न्यायालयों ने भी इस पर गंभीर टिप्पणियां की हैं। भाजपा राष्ट्रीय कार्यकारिणी निम्न मांगें करती हैं:–

1. एन आई ए, सीबीआई और अन्य एजेंसियों द्वारा तुरन्त जांच की जानी चाहिये और सभी दोषियों पर मुकदमा चलाया जाना चाहिये, जिसके लिए स्पेशल फास्ट ट्रैक न्यायालय गठित किये जायें।
2. इन सभी घोटालों की विशेष लेखा परीक्षा (आडिट) की जानी चाहिये।
3. मुख्यमंत्री और नौकरशाहों सहित सभी घोटालेबाजों की सम्पत्ति जब्त की जानी चाहिये।

पूर्वोत्तर में सामरिक सुरक्षा

जैसा कि पहले बताया गया है कि समूचे पूर्वोत्तर की एक बहुत ही विचित्र भूराजनीतिक स्थिति है। पूर्वोत्तर की अर्थव्यवस्था प्रभावी रूप से क्षेत्र के बाहर से आयतित सामग्रियों पर निर्भर है जहां पर किसी भी क्षेत्र की आर्थिक जीवन रेखा को किसी स्टेट अथवा नान–स्टेट एक्टर द्वारा बहुत आसानी से काटा जा सकता है। चीन के अत्यधिक विस्तारवादी इरादे विशेषरूप से सीमाओं के बारे में और उसके अरूणाचल राज्य, जो भारत का एक अभिन्न अंग है और रहेगा, पर उसका द्वेषपूर्ण दावा निरन्तर चिंता का विषय बने हुए हैं। ब्रह्मपुत्र नदी पूर्वोत्तर की जीवनरेखा है और ब्रह्मपुत्र नदी के स्रोत पर अनेक बांधों का निर्माण करने के चीन के कथित निर्णय से समूचे क्षेत्र के आर्थिक और सामाजिक जीवन पर गंभीर प्रभाव पड़ेगा। भारत सरकार को पूर्वोत्तर के हितों को ध्यान में रखकर इन बांधों से पड़ने वाले प्रभाव का उचित मूल्यांकन करना चाहिये। चरम पंथ, अलगाववाद और आतंकवाद क्षेत्र में अनिश्चितता की स्थिति पैदा करने में अपनी अपनी भूमिका निभाते हैं। पड़ोसी बंगलादेश में आई.एस.आई द्वारा प्रायोजित बहुत ही प्रभावी जेहादी संगठनों के पूर्वोत्तर में कार्यरत अलगावादी दलों के साथ अपने स्वयं के संबंध हैं और उन्हें उनसे सहायता मिल रही है जिससे एक गंभीर खतरा बना हुआ है। उसका दृढ़ता से मुकाबला करना होगा।

यह निश्चय ही ध्यान देने योग्य है कि जब असम विधानसभा के चुनाव बहुत नजदीक हैं, हम फिर से उल्फा नेताओं के एक वर्ग ओर सरकार के बीच बातचीत की बात सुन रहे हैं। यह जगजाहिर बात है कि कांग्रेस ने भूतकाल में अपनी चुनावी सम्भावनाओं को बेहतर बनाने के लिए उल्फा तत्वों का खुले और अप्रत्यक्ष तौर से समर्थन किया। निःसन्देह जिसका असर विदेशनीति पर भी पड़ा। हम समझते हैं कि भूटान की सरकार इस प्रकार के गतिविधियों से खुश नहीं है, वह पहले ही भारत सरकार से यह निवेदन कर चुकी है, भूटान ने अपने जंगलों में छिपे उल्फा तत्वों पर कड़ी सैनिक कार्रवाई की। इस प्रकार की गतिविधियों से बांग्लादेश की तरफ भी अच्छा संकेत नहीं जायेगा। क्योंकि एक तरफ तो भारत बांग्लादेश में उपस्थित उल्फा तत्वों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग करता है और दूसरी तरफ वह इन तत्वों से तदर्थ तौर पर और पारदर्शिता के नितांत अभाव में शांति वार्ता की बात कर रहा है। कुछ उल्फा नेताओं को छोड़े जाने का कारण भी पता नहीं चला है। भाजपा का स्पष्ट मत है कि उल्फा के किसी प्रकार की शांति वार्ता हमारे संविधान के मापदण्ड के अन्दर होनी चाहिए और यह वार्ता लम्बे समय में ऐसे पारदर्शी माहौल में सम्पन्न होनी चाहिए, जहां हिंसा और सैन्य संघर्ष की कोई जगह न हो। कांग्रेस द्वारा चुनाव को ध्यान में रखकर की गई कोई भी पहल भर्त्सना के योग्य है।

अतः पूर्वोत्तर में सुरक्षा संबंधी मुद्दे को न केवल नीति–निर्धारण की दृष्टि से देखा जाना चाहिये बल्कि इसे विदेशी मामलों, सेना, आन्तरिक एवं सामरिक सुरक्षा को जोड़कर तथा आर्थिक मुद्दों के अर्थपूर्ण समाधान के रूप में देखा जाना चाहिये। जब भाजपा के नेतृत्व में राजग केन्द्र में सत्ता में था तो उसने पूर्वोत्तर मामलों से संबंधित एक विभाग का गठन किया था और अन्य अनेक उपाय भी इस संबंध में किये थे। सुरक्षा संबंधी पहलू भी समान रूप से महत्वपूर्ण है। एक सुरक्षित और संरक्षित पूर्वोत्तर भारत के लिये महत्वपूर्ण है। समूचे पूर्वोत्तर में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के पूर्ण कमान और नियंत्रण के अन्तर्गत सुरक्षा संबंधी मुद्दों पर उचित समन्वय होना चाहिये। केन्द्र को इस प्रकार के समन्वय को उचित तरीके से सुनिश्चित करने के लिये पर्याप्त कदम उठाने चाहिये।

अंत में यह बहुत महत्वपूर्ण है कि केन्द्र और राज्य सरकार यह सुनिश्चित करे कि उत्तर–पूर्व क्षेत्र जो दिल्ली से लगभग 1600–2000 कि.मी. दूर है और इसके बहुत से क्षेत्र ऐसे हैं जहां पहुंचना दुर्गम है, ऐसे उत्तर–पूर्व क्षेत्र को आधारभूत संरचना के विकास और क्षमता निर्माण के लिए उचित समर्थन दिया जाना चाहिए। राष्ट्रीय राजमार्ग कार्यक्रम को राजग के शासनकाल के दौरान उत्तर–पूर्व क्षेत्र तक बढ़ाने की योजना थी। लेकिन उसे अब ठण्डे बस्ते में डाल दिया गया है। यह बेहद खेदजनक है। ■

2010
भ्रष्टाचार का वर्ष

गुवाहाटी (असम) में सम्पन्न भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक में लोकसभा में विपक्ष की नेता श्रीमती सुषमा स्वराज ने 'राजनीतिक प्रस्ताव' रखा, जिसका अनुमोदन राज्यसभा में विपक्ष के नेता श्री अरूण जेटली ने किया, यह प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया गया। इस प्रस्ताव में भ्रष्टाचार से सख्ती से निपटने का संकल्प किया गया। प्रस्तुत है प्रस्ताव का पूरा पाठः–

सन् 2010 की समाप्ति पर कांग्रेस नेतृत्व वाला यूपीए–2 सभ्य देशों के बीच भारत को एक असंतोषजनक ढंग से संचालित, लापरवाही भरे शासन और बेतहाशा भ्रष्ट देश के रूप में खड़ा करने के लिए जिम्मेदार है। सन् 2010 ने देखा कि कैसे कांग्रेस भारत की जनता के प्रति इतनी जबाबदेही से बचने के अहंकार से ग्रसित है कि यह घोर भ्रष्टाचार, जिसमें से तीन ने सरकारी खजाने को बहुत नुक्सान पहुंचाया है, की जांच से कतरा रही है। इन प्रत्येक तीनों घोटालों –कॉमनवेल्थ ग्रेम्स, 2जी स्पेक्ट्रम और आदर्श सोसायटी – में निजी लाभ के लिए सत्ताधीशों और निजी ऑपरेटरों की मिलीभगत साबित हुई है। व्यवस्था में से नियंत्रण और संतुलन को सुनियोजित ढंग से इस प्रकार दूर कर दिया गया जिससे इतने व्यापक और विशाल भ्रष्टाचार का रास्ता खुला। इन सबने देश को सन्न कर दिया है।

यहां गुवाहाटी में जनवरी 2011 में, भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी व्याप्त राजनीतिक माहौल को 23 वर्ष पूर्व जनवरी 1988 में एर्णाकुलम में हुई कार्यकारिणी की बैठक के समान पाता है। तब इसने कहा था, "....लगातार कई पर एक घृणित घोटालों का भंडाफोड़ हुआ, जिससे मजबूर होकर देश के प्रधानमंत्री को भी संसद में खड़े होकर यह घोषणा करनी पड़ी कि न तो उन्हें और न ही उनके परिवार को रिश्वत का कोई धन मिला है। फिर भी आम आदमी को उनकी बात पर विश्वास नहीं हुआ।"

हमने आगे और कहा कि "सरकार की विश्वसनीयता शून्य रह गई है" और कि "सरकार जांच समाप्त करने के उद्देश्य से एक ऐसी लुंज–पुंज समिति से करा रही है जो सभी प्रभावी अधिकारों से वंचित है...." तब भाजपा ने दर्ज किया था "संस्थाओं को कमजोर करना" और कहा कि "सरकार ...शीर्ष पदों के भ्रष्टाचार से ध्यान हटाने के लिए निचले स्तर पर साम्प्रदायिकता को लाने के उद्देश्य से साम्प्रदायिकता और अलगाववाद को बढ़ावा दे रही है।" और महत्वपूर्ण रूप से यह भी कहा था कि "श्रीमान स्वच्छ (श्री राजीव गांधी) श्रीमान विनाश बन कर उभरे हैं, और प्रतिदिन देश को एक घोटाला दे रहे हैं। देश को उन अदृश्य लोगों द्वारा चलाया जा रहा है जिनके बहुआयामी रहस्यमयी विदेशी सम्पर्क हैं।"

सन् 2010 में आज के प्रधानमंत्री भी प्रत्येक दिन एक घोटाला कर रहे हैं। भ्रष्टाचार के मामलों की सम्पूर्ण जांच की प्रत्येक मांग को सरकार अधिकारविहीन जांच समिति (शुंगलू और न्यायमूर्ति पाटिल) नियुक्त करके दबा रही है। अनेक रहस्यमयी विदेशी सम्पर्कों वाले अदृश्य लोग राडिया टेप और टेक्स हैवेन्स से उभरे हैं; और सीबीआई विलम्ब से उनकी तलाश कर रही है।

बोफोर्स की वापसी

1987 की तुलना में भ्रष्टाचार के आयाम कांग्रेस ने समय के साथ बढ़ने दिया है। चूंकि परिस्थितियों की मांग है इसलिए बोफोर्स मामले में क्वात्रोची के महत्व का स्मरण

करना उचित होगा। जब श्री राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे तब श्री क्वात्रोची का उनके घर में खुला प्रवेश था। साथ ही उस समय की सत्ता के साथ उनके सम्बन्धों को मीडिया ने भी प्रकाशित किया था। घोटालों के सोपानों में बोफोर्स घोटाला इसलिये महत्व पा सका कि श्रीमान क्यू के तब के प्रधानमंत्री से घरेलू रिश्ते थे।

कांग्रेस पार्टी ने उसको बचाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी और निष्पक्ष जांच के हर प्रयास को नष्ट किया। तमाम विरोधों के बावजूद वे इस गलत काम पर लीपापोती करने पर जोर देते रहे। यह लीपापोती इस एक बात पर आधारित थी–बोफोर्स सौदे में कोई दलाली नहीं दी गई। अब बोफोर्स फिर से इस आधार को झुठलाते हुए वापस उभरा है। वस्तुत दलाली दी गई।

आयकर अपीलीय ट्रिब्यूनल ने प्रमाणित किया है कि वास्तव में मिस्टर क्वात्रोची और अन्यों ने दलाली की रकम प्राप्त की तथा इस रकम को कर से बचाने के लिए एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र ले जाया गया। कांग्रेस पार्टी ने लगातार यह दलील दी कि कोई दलाली नहीं दी गई और इसलिए क्वात्रोची के विरूद्ध केस बंद किए गए।

कांग्रेस, विशेष रूप से शाही परिवार को सत्य की शक्ति का सामना करना पड़ रहा है। असुविधाजनक समय पर प्रकट होने की आदत से सत्य मजबूर हैं। इस केस को दबाने के लिए सीबीआई का प्रत्येक समय और प्रत्येक स्तर पर दुरूपयोग कर क्वात्रोची को देश से बाहर भाग निकलने दिया गया। विदेशों में भी हमारे देश के कानूनों से उसे बचाने के लिए हमारी एजेंसियों ने विदेशी अदालत में या तो कमजोर केस प्रस्तुत किया या देर से हलफनामे दायर किए। हमारे राष्ट्रीय हितों के इस अपराधी को बचाने के लिए कांग्रेस ने बेशर्मी की हद कर दी। आज सीबीआई कह रही है "हमने केस खत्म कर दिया और इसलिए कोई केस नहीं है।"

2जी स्पेक्ट्रम घोटाला- सर्वाधिक चर्चित एवं राष्ट्रीय हानि

2जी स्पेक्ट्रम केस अब तक का देश में सबसे बड़ा घोटाला है। इसका आकार, इतना विशाल है कि आने वाले दशकों में भी कोई इसे पीछे नहीं धकेल सकता। आश्चर्य यह है कि मीडिया और राजनीतिक दल पिछले 2 वर्षों से फल–फूल रहे इस घोटाले के विरूद्ध कार्रवाई करने की मांग कर रहे थे तब भी इसे रोका नहीं गया। चूंकि प्रधानमंत्री को यूपीए–2 गठबंधन को जोड़े रखना था इसलिए चाहे जो हो घोटाला करने वालों को संरक्षण दिया गया। सरकारी खजाने को होने वाले नुकसान कम से कम 95000 करोड़ रूपए और ज्यादा से ज्यादा 1,76,000 करोड़ रूपए हुआ है। देश को होने वाले नुक्सान का आकलन करने के लिए सीएजी ने दस्तावेजों के आधार पर फार्मूला निकाला है। इन आकलनों पर प्रश्न उठाना और या संभावित नुक्सान वर्णित करना सीएजी की कार्यदक्षता का मजाक उड़ाना है। दलालों की कीमत, और घोटाला करने वालों द्वारा प्राप्त किया गया हिस्सा और इसे कहां रखा गया है, की आगे जांच होनी है। इस धन की वापसी चुनौती भरा काम सिद्ध होगा।

प्रधानमंत्री की 'कुछ नहीं करने' की नीति ने मामले को नियंत्रण से बाहर जाने में सहायता की है। इस सबका मूकदर्शक बने रहकर जहां प्रधानमंत्री ने भारत के लोगों की नजरों में प्रधानमंत्री के पद की गरिमा गिराई है वहीं राष्ट्र को लुटने दिया।

नेशनल इंवेस्टिंग एजेंसी (एन आई ए) ने अपने पहले केस में नार्थ कछार हिल्स ऑटोनोमस काउंसिल (एनसीएचएसी) में 1000 करोड़ रूपए का घोटाला पकड़ा है। हालांकि एनआईए ने चुप्पी साधी हुई है, परन्तु 'द वीक' पत्रिका ने बताया है कि अनेक नौकरशाहों के अलावा असम के सात मंत्री –एनआईए ने चिन्हित किए हैं जो इस घोटाले से लाभान्वित हुए हैं। तथ्य यह है कि सीबीआई द्वारा तत्पश्चात मारे गए छापे में एक नौकरशाह के रिश्तेदार के घर से 13.45 करोड़ रूपए बरामद किए गए हैं।

कॉमनवेल्थ गेम्स घोटाला

2010 के राष्ट्रमंडल खेलों के आयोजन के अवसर को कांग्रेस पार्टी के अंतरंग मित्रों ने अपनी लालसा को बढ़ावा देने के रूप में उपयोग किया। भ्रष्टाचार, अनियमितताओं, शोचनीय गुणवत्ता, खेलों के उद्घाटन से पहले तक विलम्बित और आधे–अधूरे कामों से राष्ट्र को शर्मिन्दगी उठानी पड़ी।

प्रधानमंत्री कार्यालय को अनुचित बढ़ी कीमतों पर राजी करना और भाईभतीजावाद में शामिल कर लिया गया। अयोग्य परन्तु ऊंचे रसूख वालों को विशेषीकृत कुशलता वाले काम भी दे दिए गए। कहने की जरूरत नहीं कि राष्ट्र को अपमानजनक अवस्था में डाला गया। एक अधिकारविहीन समिति (शुंगलू कमेटी) गलतियों की जांच कर रही है जबकि समूचे दस्तावेज साक्ष्य जनता के सामने उपलब्ध हैं।

कारगिल युद्ध की विधवाओं से विश्वासघात

आदर्श सोसायटी घोटाला इस देश की आत्मा पर चोट

पहुंचाने वाला है। जो भूमि कारगिल युद्ध में शहीदों की विधवाओं के लिए थी उसे कुछ उच्च पदों वाले सैन्य अधिकारियों ने शक्तिशाली नौकरशाहों और उनके राजनीतिक आकाओं की सांठ–गांठ से हथिया ली। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को इसलिए इस्तीफा देना पड़ा क्योंकि इस आवंटन में उनकी सास और अन्य निकट के रिश्तेदारों को फायदा पहुंचा। यह घावों पर नमक छिड़कना ही है कि पुलिस थाने में एक एफ आई आर दर्ज कराई गई कि मुख्यमंत्री के हस्ताक्षरों वाली आदर्श सोसायटी संबंधी फाइल गुम हो गई है। पहले भूमि और फिर प्रमाण– दोनों ही शहीदों की विधवाओं के हाथों से निकल गए। इतनी अधिक जनता के सामने, मुख्यमंत्री कार्यालय से संबंधित फाइल गायब हो जाने को कांग्रेस की बेशर्मी ही कहा जाएगा।

2जी, कॉमनवेल्थ गेम्स और आदर्श घोटाले में कार्यपालिका और विधायिका के अन्य अनेक पहलू जुड़े है – नीति और निर्णय प्रक्रिया सम्बन्धी मामलों में कॉरपोरेट लॉबिंग, सिस्टम में मौजद नियंत्रण और संतुलन को सावधानीपूर्वक हटाना (स्पष्टतया मंत्री स्तर पर भी) नियंत्रण प्राधिकरण को अप्रासंगिक बताना इत्यादि। पीएसी के लिए इन जटिलताओं में जाना संभव नहीं है। पीएसी मंत्रियों को नहीं बुला सकती।

कांग्रेस-शासित असम में भ्रष्टाचार

भ्रष्टाचार कांग्रेस शासित प्रदेशों में व्याप्त है। चूंकि भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी प्रागज्योतिषपुर में हो रही है इसलिए यहां की कांग्रेस सरकार के बारे में बोलना समीचीन है। नेशनल इंवेस्टिंग एजेंसी (एन आई ए) ने अपने पहले केस में नार्थ कछार हिल्स ऑटोनोमस काउंसिल (एनसीएचएसी) में 1000 करोड़ रूपए का घोटाला पकड़ा है। हालांकि एनआईए ने चुप्पी साधी हुई है, परन्तु 'द वीक' पत्रिका ने बताया है कि अनेक नौकरशाहों के अलावा असम के सात मंत्री –एनआईए ने चिन्हित किए हैं जो इस घोटाले से लाभान्वित हुए हैं। तथ्य यह है कि सीबीआई द्वारा तत्पश्चात मारे गए छापे में एक नौकरशाह के रिश्तेदार के घर से 13.45 करोड़ रूपए बरामद किए गए हैं।

इसी प्रकार यह पाया गया है कि गुवाहाटी के लिए जवाहरलाल नेहरू अर्बन रिन्यूबल मिशन के कोष में से बहुमंजिला पार्किंग, ड्रेनेज़ और पेयजल जैसी परियोजनाओं के नाम से 200 करोड़ रूपए की राशि बेईमानी से हड़प ली गई है।

अरूणाचल में भी घपला

अरूणाचल प्रदेश में कांगेस सरकार पर आरोप है कि वह ट्रांसपोर्ट सबसिडी का दुरूपयोग कर रही है। मीडिया ने केवल दो चीजों : सीमेंट और लोहा एवं इस्पात में भी ट्रांसपोर्ट सबसिडी के 682 करोड़ रूपए के घोटाले का पर्दाफाश किया है। ये सभी भ्रष्टाचार भरे घोटाले अपने आप में चिंतनीय है : प्रधानमंत्री के विशेषाधिकार में कॉरपोरेट लॉबिस्टों द्वारा निभाई गई भूमिकाएं गंभीर मामला है। मंडिमंडल बनाना और केबिनेट के सदस्यों को मंत्रिमण्डलीय पदों का आबंटन प्रधानमंत्री के विशेषाधिकार में आते हैं। यूपीए द्वितीय के मामले में तो प्रधानमंत्री से यह विशेषाधिकार भी उन लॉबिस्टों ने छीन लिया जो एक समय पर अनेक कॉरपोरेट हाऊसों के लिए काम कर रहे थे। मीडिया में से भी कुछ इस खेल में शामिल थे।

संस्थाओं का उल्लंघन

मुख्य सतर्कता आयोग (सीबीसी) की नियुक्ति, लोकसभा में विपक्ष की नेता श्रीमती सुषमा स्वराज की लिखित आपत्तियों को नजरअंदाज करके की गई। सीबीसी के विरूद्ध लगभग 10 वर्षों से केरल में भ्रष्टाचार का केस लम्बित है। दिसम्बर 2009 में टेलीकॉम सचिव के रूप में जब सीएजी ने सम्बन्धित फाइल मांगी तो उन्होंने जवाब दिया कि उनके पास कोई फाइल नहीं है और सुझाया कि सीएजी सीबीआई से मांग सकते है। इतना ही नहीं जुलाई 2010 में सीबीसी ने अपने हस्ताक्षरों से एक पत्र भेजकर सीएजी से उसके अधिकारों पर सवाल उठाए है। यहां तक कि उनके पद पर रहते औचित्य के मुद्दे पर बहस के चलते सीबीसी ने सीबीआई का नया प्रमुख नियुक्त कर दिया जो 29 घोटालों की जांच करेगा। हमारी संस्थानों का कैसा मजाक उड़ाया जा रहा है।

जेपीसी की तत्काल जरूरत

राष्ट्र के सामने मुंह बाए खड़े तीन मुख्य भ्रष्टाचार घोटालों के स्वरूप और पेचीदगी को ध्यान में रखते हुए भाजपा इनकी जांच संयुक्त संसदीय समिति से कराने की मांग कर रही है।

लोक लेखा समिति जैसा संवैधानिक निकाय सरकारी खजाने को हुए नुक्सान और विभागीय निर्णयों की असफलताओं की तह में जा सकता हैं निस्संदेह ! टेलीकाम ऐसा ही एक मंत्रालय है जिसका अध्ययन सीएजी की रिपोर्टों के आधार पर लोक लेखा समिति कर रही है। अतः क्या यह अन्य मंत्रालयों का भी अध्ययन करती है : निश्चित ही, यह उसका

काम है कि वह सीएजी रिपोर्टों के माध्यम से सरकारी कोष से व्यय होने वाले प्रत्येक रूपए की जांच करें और उत्तरदायित्व सुनिश्चित करे।

लेकिन 2जी, कॉमनवेल्थ गेम्स और आदर्श घोटाले में कार्यपालिका और विधायिका के अन्य अनेक पहलू जुड़े है – नीति और निर्णय प्रक्रिया सम्बन्धी मामलों में कॉरपोरेट लॉबिंग, सिस्टम में मौजद नियंत्रण और संतुलन को सावधानीपूर्वक हटाना (स्पष्टतया मंत्री स्तर पर भी) नियंत्रण प्राधिकरण को अप्रासंगिक बताना इत्यादि। पीएसी के लिए इन जटिलताओं में जाना संभव नहीं है। पीएसी मंत्रियों को नहीं बुला सकती। प्रधानमंत्री ने बहादुरी से पीएसी के सामने पेश होने की पेशकश की है लेकिन तत्पश्चात् पीएसी इसे संभव बनाने के रास्ते खोजती नजर आ रही है।

मिलकर हम इस शानदार राष्ट्र को भ्रष्टाचार, लालच और लूट की कांग्रेसी संस्कृति से मुक्त कराने के लिए लड़ेंगें। दुनिया के किन्हीं भी टैक्स हैवन्स में ले जाए गए काले धन को वापस लाया जाना चाहिए। इस असाध्यकार्य के लिए राजनीतिक इच्छा और राष्ट्रीय हितों की आवश्यकता है।

जेपीसी निश्चित और उसका निर्देशपद व्यापक होने चाहिए। सिर्फ भ्रष्टाचार इसका विषय होना चाहिए तथा यह उसकी तार्किक कड़ियों, जो चाहे जितनी गहरी, दूर या डरावनी हो, का पता लगा सकें। इस उद्देश्य के लिए इसे उन सभी को बुलाकर पूछताछ करनी चाहिए जो चाहें कितने भी शक्तिशाली क्यों न हों। और ठीक इसी बात से कांग्रेस जेपीसी से डरी हुई है। और इसलिए वह यह नहीं चाहती और वे अपने हठ पर अड़े हुए है।

देश में अत्यधिक हताशा और अविश्वास व्याप्त है। राजनीतिज्ञों पर से लोगों का भरोसा उठ गया है। और राजनीतिक दलों से भी उन्हें कोई आशा नहीं बची हैं। उन्हें लगता है कि यदि वे न्यायालयों के माध्यम से सही फैंसले पा लेंगे तो आश्चर्य होगा। मूक प्रधानमंत्री से स्थिति में कोई सुधार नहीं है।

प्रागज्योतिषपुर की इस वीर भूमि में भारतीय जनता पार्टी संकल्प करती है कि वह भ्रष्टाचार से पूरी तरह से लड़ेगी। लोगों के खोए भरोसे की वापसी के लिए भाजपा इस प्रयास की धुरी बनेगी। बहुत समय नहीं हुआ जब हमारा जन्म संघर्षों में से हुआ, जो लोग, समूह, नागरी अधिकार संगठन और दल 'भ्रष्टाचार से मुक्त भारत' चाहते है, उन्हें मिलकर यह प्रयास करना चाहिए। मिलकर हम इस शानदार राष्ट्र को भ्रष्टाचार, लालच और लूट की कांग्रेसी संस्कृति से मुक्त कराने के लिए लड़ेंगें। दुनिया के किन्हीं भी टैक्स हैवन्स में ले जाए गए काले धन को वापस लाया जाना चाहिए। इस असाध्यकार्य के लिए राजनीतिक इच्छा और राष्ट्रीय हितों की आवश्यकता है। इस परेशानी भरे राजनीतिक माहौल में, भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी संकल्प लेती है:

कांग्रेस पार्टी के बेतहाशा भ्रष्टाचार के विरूद्ध लोगों का ध्यान आकृष्ट करने के लिए देश के सभी भागों के विभिन्न स्थानों पर रैलियां आयोजित करेगी।

भ्रष्टाचार की बुराई के विरूद्ध जागृति लाने के उद्देश्य से जीवंत इंटरनेट समुदाय को मजबूत बनाने में सहायता करना और दुनियाभर में भ्रष्टाचार की इस बुराई को समाप्त करने के लिए विभिन्न संस्थानों में दबाव समूहों के रूप में कार्य करना। आम आदमी से जुड़े मुद्दों – मुख्य रूप से मंहगाई को नियंत्रित न कर पाने –के विरूद्ध सरकार की असफलताओं को उजागर करना।

न्याय के लिए कानूनी रास्ता अपनाना – ताकि राष्ट्र को लूटने वालों को दण्डित किया जा सके और जो यहां से विदेशों के विभिन्न टेक्स हैवन्स में जो धन ले जाया गया है उसे वापस लाया जा सके। ■

जम्मू कश्मीर पर अध्ययन दल

भाजपा का 'जम्मू-कश्मीर' सम्बन्धी अध्ययन दल गठित

जम्मू कश्मीर की विशेष परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नितीन गडकरी जी ने जम्मू की राष्ट्रीय पदाधिकारी बैठक में अध्ययन दल भेजने की घोषणा की थी। उसी क्रम में पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राजनाथ सिंह जी के नेतृत्व में समिति की घोषणा की है जो निम्न है–

श्री राजनाथ सिंह	पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष
श्री रविशंकर प्रसाद	राष्ट्रीय महामंत्री
श्री शाहनवाज हुसैन	राष्ट्रीय प्रवक्ता
श्रीमती माया सिंह	मुख्य सचेतक राज्यसभा
श्री डॉ0 जे.के. जैन	प्रभारी अल्पसंख्यक मोर्चा

यह दल जम्मू, कश्मीर घाटी, लद्दाख– कारगिल सहित प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों के सभी वर्गो से चर्चा कर पार्टी के समक्ष जानकारी रखेंगें। ■

भाजपा राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक सम्पन्न

आंध्र प्रदेश, उडीसा और महाराष्ट्र में भारी वर्षा ने तबाही मचा दी। खेद है कि राज्य सरकारें और केन्द्र सरकार किसानों को राहत तक नहीं दे सकीं

Hkkजपा राष्ट्रीय पदाधिकारियों की यह बैठक आंध्र प्रदेश के किसानों की बदहाली पर अपनी गहन चिंता व्यक्त करती है, जो जुलाई और दिसम्बर 2010 के बीच असामयिक और निरंतर वर्षा होने के कारण उन पर बरपी विनाशलीला से आज पूरी तरह हताशा के सागर में डूबे हुए हैं। किसानों की यह दयनीय दशा देख कर उसका अनुमान तक लगाना बेहद मुश्किल कार्य है। वे पूरी तरह से बर्बाद हो गए हैं क्योंकि उनकी फसलें, मुख्य रूप से धान की फसल बारिश के सागर में बह गई है। अभी वे अपनी गाढी मेहनत से कमाई गई अपनी फसल का लाभ चखने ही वाले थे कि निर्मम मौसम ने उनके हाथों से सब कुछ छीन लिया। किसानों के दुखों का तो कोई अंत ही नहीं रहा जब हमने देखा है कि किसानों की फसलों के भारी नुकसान से अभी वे उबरे भी नहीं थे कि तभी भारी वर्षा ने कहर ढा दिया, जो 2009 और फिर 2010 में ''लैला'' और ''जल'' के तूफानों के रूप में परिणत हुआ है।

धान की 25 लाख से अधिक तथा तम्बाकू, कपास, हल्दी, प्याज, मिर्ची, काला चना, लाल चना, मूंगफली जैसी 10 लाख एकड़ से अधिक की वाणिज्यिक फसल पर ग्रहण लग गया और किसान राज्य और केन्द्र सरकार से तुरन्त ही राहत पाने के लिए उनकी ओर निहारते रहे।

बुनकर और मछुआरों पर भी गहरा असर पड़ा क्योंकि पानी बुनकरों के करघों में घुस गया तो उधर मछुआरों की छोटी–छोटी नावें पानी में बह गई। इससे उनके जीवनयापन के साधन ही खत्म हो गए।

दिसम्बर से अब तक 300 से अधिक किसान आत्महत्या कर चुके हैं। और इस दयनीय स्थिति को देख कर भी अभी तक सरकार पूरी तरह से बेखबर पड़ी हुई है। यह देख कर अत्यंत दुख होता है कि न तो प्रधानमंत्री और न ही सत्ताधारी गठबंधन अध्यक्षा और न ही कृषि मंत्री के पास प्रभावित किसानों के पास जाने तक का समय नहीं है और न ही वे उन्हें सांत्वना दे रहे हैं।

श्री लालकृष्ण आडवाणी के नेतृत्व में भाजपा के एक शिष्टमण्डल ने, जिसमें श्रीमती सुषमा स्वराज, श्री अरूण जेटली, श्री वेंकैया नायडू श्री गोपीनाथ मुण्डे और श्री पुरूषोत्तम रूपाला शामिल थे। 13 दिसम्बर 2010 को प्रधानमंत्री से मिले और उसके बाद कृषि मंत्री से मिले। भाजपा ने किसानों को समय पर मदद और राहत प्रदान करने के लिए अनेक रचनात्मक सुझाव दिए। परन्तु दुर्भाग्यवश, यह देखकर अफसोस होता है कि आज तक भी न तो केन्द्र ने और न ही राज्य सरकार ने इस गम्भीर स्थिति पर कोई कार्रवाई की। केन्द्र और राज्य दोनों सरकारों ने किसानों की इस भयावह बदहाली और 'कैज्युअल' रूख

बनाए रखा है पर अब तो राज्य के किसानों में आक्रोश और व्यथा बढ़ती चली जा रही है।

किसानों को राज्य और केन्द्र दोनों सरकारों से उदार सहायता की आवश्यकता है। राज्य सरकार द्वारा घोषित पैकेज एकदम अपर्याप्त है और इससे किसानों को घोर बर्बादी का समाधान होने वाला नहीं है।

अब तो किसान आंदोलन के रास्ते पर है। भाजपा भी अपने ढंग से सरकार पर दबाव डालने के लिए इस घोर दुर्दशा को समझने के लिए निरंतर सार्वजनिक आंदोलनों का सहारा ले रही है ताकि किसानों को पर्याप्त और न्यायसंगत मदद मिले।

किसान 10000 रूपए प्रति एकड़ के हिसाब ने इनपुट सब्सिडी की मांग कर रहे हैं; वे चाहते हैं कि एक वर्ष की स्थगनावधि पर ऋणों की वापसी का पुनर्निर्धारण किया जाए और सरकार द्वारा ब्याज की अदायगी की जाए। किसान आगे की फसलों की बुवाई के लिए भी नए ऋण चाहते हैं।

किसान चाहते है कि भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) बाजार में प्रवेश कर बदरंग, क्षतिग्रस्त, अंकुरित और घुन लगे अनाज की खरीदारी करे और बदरंग चावल को भी 'बाइल्ड' चावल में परिवर्तित करे और इसके लिए निर्यात की अनुमति दी जाए। परन्तु दुर्भाग्यवश, एफसीआई ने अभी तक बाजार में प्रवेश नहीं किया है और केवल 10 प्रतिशत की ढील दी गई है और इसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त प्रतिशत के लिए 10 रूपए की कटौती की जाएगी। इसका मतलब यह हुआ कि यदि किसान की फसल का 50 प्रतिशत चावल बदरंग है तो उसे मूल्य कटौती के रूप में प्रति क्विंटल 500 रूपए का नुकसान उठाना पडेगा। यह किसी भी तरह से न्यायोचित नहीं है और बेतुका है। न तो एफसीआई और न ही सिविल आपूर्ति विभाग प्रभावित धान की खरीद कर रहे हैं। किसानों के पास कोई विकल्प नहीं बचा है सिवाए इसके कि वे औने–पौने दामों में इसे बेच दें। अभी तक सरकारी एजेंसियों ने 100 लाख टन के अनुमानित भण्डार में से केवल 3500 टन का धान ही खरीदा है।

बीपीटी 5204 किस्म के चावल के पुराने स्टाक को निर्यात की अनुमति देकर बिक्री किए जाने की आवश्यकता है।

वर्ष 2003 में इसी प्रकार की कम आपदा वाली स्थिति में भी राजग सरकार ने बिना किसी मूल्य कटौती के नमी वाली फसलों में 20 प्रतिशत तक की आद्रता में ढील दी थी। इस वर्ष भी छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और कर्नाटक जैसे भाजपा शासित राज्यों में धान किसानों को अतिरिक्त बोनस प्रदान कर लाभकारी कीमत प्रदान की है।

तम्बाकू उत्पादक प्रति खत्ता 1 लाख रूपए का अतिरिक्त ऋण चाहते हैं और वे अतिरिक्त फसल उगाने पर दिए गए जुर्माने की वापसी भी चाहते हैं। यह देखकर हैरानी होती है कि तम्बाकू बोर्ड की सिफारिशों के बावजूद भी वाणिज्य मंत्री मंजूरी न देकर इस फाइल पर चुपचाप बैठे हुए हैं।

किसान निकास प्रणाली व्यवस्था के आधुनिकीकरण पर चरणबद्ध ढंग से योजना पर कार्रवाई चाहते हैं क्योंकि इस व्यवस्था की असफलता के कारण ही इतने बड़े पैमाने पर बर्बादी देखने को मिली है।

यूनिट के रूप में किसान की व्यक्तिगत जोत वाली व्यापक फसल योजना बीमा कार्यान्वित किए जाने की आवश्यकता है।

भाजपा इस बर्बादी को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने के पक्ष में हैं।

भाजपा का मानना है कि ये सभी मांगें न्यायोचित हैं और यह भी कि केन्द्र द्वारा घोषित राहत जहां एक तरफ 'अत्यंत कम' है, वहीं दूसरी तरफ इसमें बहुत देर की गई है। आपदा आकस्मिक निधि से जारी 400 करोड़ रूपए की राशि मात्र दिखावा है क्योंकि इतनी राशि तो एनसीसीएफ से आंध्र प्रदेश को पहले ही बकाया थी।

केन्द्र सरकार किसान विरोधी रवैया अपना रहा है और इसके फलस्वरूप उसे परिणाम भुगतने पड़ेंगे। भाजपा ने प्रभावित किसानों की न्यायोचित मांगों के समर्थन में आंदोलन तीव्र करने का निर्णय लिया है।

Hkktik Hkkjr ljdkj ls vkxzg djrh gS fd og bl fLFkfr dh xEHkhjrk dks n[krs gq, rRdky dkjZokbZ djs vkSj fdlku lenk; ds nq[kksa dks lekIr djus ds fy, i;kZIr ,oa lkFkZd unkfud mik; 'kq: djsA cSal fdlkuksa dh grk'kk fdlh Hkh rjg jk"Vªfgr esa ugha gSA Hkktik dsUnz ljdkj ls rqjar dkjZokbZ dh ekax djrh gS] ,sls u gks foyEc djuk ?kkrd fl) gks tk,A blls vkèkz izns'k ds yksxksa dk vkØks'k c<+rk pyk tk,xkA

भाजपा मांग करती है कि भारत सरकार तुरंत ही एफसीआई को बदरंग धान के नमूनों में ढील देने का निर्देश दे ताकि बाजार में तेजी आए और किसानों को अपनी फसल औने–पौने दामों में न बेचनी पड़े।

भाजपा की यह भी मांग है कि केन्द्र सरकार को तुरंत ही किसानों, बुनकरों और मछुआरों की पीड़ा समाप्त करने के लिए आंध्र प्रदेश राज्य को 3000 करोड़ रूपए जारी करने चाहिए।

उड़ीसा

उड़ीसा में असामयिक भारी वर्षा के

कारण वहां के किसानों की स्थिति भी चिंतनीय है। सभी 30 जिलों में फसल प्राप्त करने के मौसम के बीच भारी वर्षा का सामना करना पड़ा है। न तो राज्य सरकार ने फसल में हुई हानि का ब्यौरा दिया है और न ही केन्द्र सरकार ने अभी तक किसानों को राहत प्रदान की है। किसानों के मुद्दे पर केवल दोषारोपण का खेल जारी है। किसान बर्बाद हो रहे हैं और उन्हें केन्द्र से अधिकतम इमदाद की आवश्यकता है।

महाराष्ट्र

महाराष्ट्र कभी कृषि मोर्चे पर देश का सबसे समृद्ध राज्य माना जाता था, जो अब किसानों की आत्महत्याओं का राज्य बन गया है। इसका कारण कांग्रेस–नीत–गठबंधन की गलत और किसान–विरोधी नीतियां हैं। इससे पूर्व किसानों की कमर सूखे ने तोड़ डाली थी और अब असामयिक वर्षा इसका कारण बन गई है जिससे किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। धान, कपास, संतरा, सोयाबीन, प्याज और अंगूर जैसी 20 लाख से अधिक की फसल बर्बाद हो गई और किसानों को भारी नुकसान हुआ है। केन्द्र ने एनसीसीएफ से केवल अग्रिम राशि जारी की है।

किसानों के प्रति केन्द्र की उदासीनता हर राज्य में एक जैसी बनी हुई है। चाहे आंध्र हो या उड़ीसा या महाराष्ट्र सभी जगह एक जैसी स्थिति है। बेचैनी बढ़ रही है और हम इतनी ही उम्मीद करते हैं कि केन्द्र सरकार तुरंत कार्रवाई करेगी, ऐसा न हो विलम्ब करना घातक सिद्ध हो जाए और काबू से बाहर हो जाए।

भाजपा महसूस करती है कि कृषि संकट के सम्पूर्ण मुद्दे पर एक नया रूख अपनाने की आवश्कता है और जरूरत है एक नई कृषि नीति अपनाने की जिससे कृषि क्षेत्र समृद्ध हो सके। ■

कर्नाटक

पंचायत चुनावों में भाजपा का परचम

'कर्नाटक सरकार के जनोपयोगी और विकासोन्मुखी कार्यक्रमों को जनता ने अपार समर्थन देकर राज्य में जिला पंचायत चुनावों में भारतीय जनता पार्टी को विजयी बनाया है। 2005 में भाजपा जहां एक जिला पंचायत में ही बहुमत में थी, वहीं 2011 के चुनाव में 12 जिला पंचायतों पर भाजपा का कब्जा हुआ है। 5 जिलों में भाजपा सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। इस चुनाव परिणाम से कांग्रेस और जद (एस) को भारी नुकसान हुआ है। पिछले चुनाव में कुल 27 जिलों में से 22 पर कब्जा रखने वाली कांग्रेस मात्र 4 जिलों में ही बहुमत सिद्ध कर पाई है। इसी प्रकार जनता दल (एस) के नेता भाजपा से अधिक जिला पंचायतों पर कब्जा जमाने की भविष्यवाणी कर रहे थे परन्तु वे भी 4 जिलों में ही सिमट कर रह गए। इस चुनाव में बारह जिलों में भाजपा, कांग्रेस चार, जद (एस) चार, शेष 10 जिलों– गुलबर्गा, बीजापुर,रायचूरु, कोप्पड, बेल्लारी, चित्रदुर्ग, कोलार, बेंगलुरु ग्रामीण, बेंगलुरु नगर एवं मैसूर में किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिला। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बी.एस.येदियुरप्पा ने जनता दल (एस) के नेताओं को आगाह किया कि वे राज्य में अस्थिरता पैदा न करें और भाजपा को भी सुगमता से सरकार चलाने में सहयोग करें। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि जो लोग भाजपा पर शहरी पार्टी होने का आरोप लगाते थे, उनकी आँखें इन चुनाव परिणामों के बाद खुल जानी चाहिए।

dy ftyk ipk;r % 30		dy rglhy ipk;r % 176	
भाजपा	12	भाजपा	68
कांग्रेस (एस)	04	कांग्रेस (एस)	31
जद	04	जद	29
त्रिशंकु	10	त्रिशंकु	48

मध्यप्रदेश

निकाय चुनाव में कमल खिला

नगरीय निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने जीत का परचम लहरा दिया। सीहोर और शाजापुर नगर पालिका कांग्रेस के कब्जे से भाजपा ने छुड़ा ली, जबकि मंदसौर नगरपालिका पर बीते 28 सालों का भाजपा का कब्जा बरकरार रहा। सीहोर नगर पालिका में आजादी के बाद पहली बार भाजपा ने परचम लहराया।

भाजपा ने पांच नगर पंचायतों में से तीन पर जीत दर्ज की है। इनमें हरपालपुर, ओरछा, शाहगंज नगर पंचायत शामिल हैं। छतरपुर जिले की हरपालपुर नपा अध्यक्ष पद पर अभिषेक राय, टीकमगढ़ जिले की ओरछा नपा अध्यक्ष पद पर प्रमोद तिवारी विजयी हुए। सीहोर जिले की शाहगंज नगर पंचायत में भी चंद्रकला मेहरा जीतीं जबकि 15 वार्डों में 12 पर भाजपा एवं 2 पर कांग्रेस 1 पर निर्दलीय पार्षद चुने गए। ■

कांग्रेस भ्रष्टाचार का पर्याय : आडवाणी

jkष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने संप्रग सरकार की गलत नीतियों से बेलगाम महंगाई और भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी महासंग्राम रैली असम राज्य की राजधानी गुवाहाटी में आयोजित की। इस रैली में राजग के कार्यकारी अध्यक्ष श्री लालकृष्ण आडवाणी, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नितिन गडकरी, लोकसभा में विपक्ष की नेता श्रीमती सुषमा स्वराज, राज्यसभा में विपक्ष के नेता श्री अरूण जेटली, भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह, राजग के संयोजक श्री शरद यादव, भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री श्री विजय गोयल, असम भाजपा अध्यक्ष श्री सजीत दत्ता, शिवसेना के आनन्द राव अदसूल और अकाली के महामंत्री श्री चन्दू मजरा सम्मिलित हुए।

रैली में उपस्थित नेताओं ने कृषक मुक्ति संग्राम की उसके साहसिक कदम के लिए प्रशंसा की। ज्ञातव्य हो कि कृषक मुक्ति संग्राम ने असम में कांग्रेसी मंत्रियों द्वारा किए गए भ्रष्टाचार को उजागर किया था। कृषक मुक्ति संग्राम के नेता अखिल गोगई का आरोप है कि मुख्यमंत्री तरूण गोगई ने भ्रष्टाचार करके अमरीका में पांच घर खरीदा है। इस भ्रष्टाचार को राजग नेता ने कांग्रेस की प्रवृत्ति बताई।

भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नितिन गडकरी ने रैली को संबोधित करते हुए कांग्रेस की गलत आर्थिक नीतियों और खराब शासन व्यवस्था के लिए भर्त्सना की। एक तरह के विचार रखने वाले व्यक्तियों और संगठनों से एक होकर इस सरकार का विरोध करने का आह्वान किया। श्री गडकरी ने असम की जनता से भाजपा को विधानसभा चुनाव में समर्थन देने की अपील की और कहा कि यदि भाजपा सत्ता में आती है तो समाज में सामाजिक और आर्थिक समानता तथा गरीबी की बीमारी को खत्म करने का प्रयास करेगी।

राजग के कार्यकारी अध्यक्ष श्री लालकृष्ण आडवाणी ने सभा को सम्बोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस भ्रष्टाचार का पर्यायवाची हो गई है और बढ़ती हुई कीमतों का एक मात्र मूल कारण भ्रष्टाचार है जिससे आम आदमी का जीना मुहाल हो गया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के भ्रष्टाचार के खिलाफ राजग ने जो अभियान छेड़ रखा है वह एक जनांदोलन का रूप ले लेगा। अपने भाषण के दौरान श्री आडवाणी ने बांग्लादेशी घुसपैठ के मामलों को उठाया और कहा कि केन्द्र सरकार को तत्परता से इस समस्या का निदान करना होगा।

श्री आडवाणी ने यूपीए की अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी की 2जी और कॉमनवेल्थ के भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए आलोचना की। उन्होंने कहा कि 2जी और कॉमनवेल्थ घोटालों ने देश को शर्मिंदा किया है।

भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राजनाथ सिंह ने उत्तर–पूर्व भारत के लोगों से आह्वान किया कि वह भ्रष्टाचार और महंगाई के खिलाफ आंदोलन में राजग को समर्थन दें। उन्होंने आश्वासन दिया कि यदि केन्द्र में हमारी सरकार आयी तो भ्रष्टाचार को मिटायेगी तथा महंगाई को नियंत्रित करेगी। उन्होंने असम के लोगों से विधानसभा चुनाव में भाजपा को मत देने की भी अपील की। ■

क्या क्वात्रोची के बारे में अपनी टिप्पणी के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्र से क्षमा मागेंगे ?

Vkयकर अपीलीय प्राधिकरण ने इतावली बिचौलिया क्ताविया क्वात्रोची को बोफोर्स गन डील में प्रमुख रूप से रिश्वत लेने वाले व्यक्तियों में से एक माना है। अपने 31 दिसम्बर 2010 के विस्तृत आदेश में उसने यह स्पष्ट कहा कि 41 करोड़ रूपये का भुगतान क्वात्रोची और विन चड्ढा को अवैधानिक रूप से किया गया। भारत सरकार के राजस्व विभाग के अन्तर्गत कार्य करने वाले इस प्राधिकृत ट्रिब्यूनल के विस्तृत सबूतों के आधार पर क्या भारत के प्रधानमंत्री राष्ट्र से अपने इस कथन के लिए क्षमा मागेंगे कि ''भारतीय विधि तंत्र का यह एक अच्छा संदेश नहीं है कि हम लोगों को परेशान करते है और कवात्रोची का उदाहरण भारत सरकार के लिए परेशानी है''। प्रधानमंत्री का यह कथन आज मीडिया में विस्तृत रूप से चर्चा में है और आयकर प्राधिकरण की विस्तृत व्याख्या इसके विपरीत है। प्रधानमंत्री ने दिखाया है कि ''Caesar's wife must be above suspicion" अतः क्वात्रोची को दोषमुक्त करते हुए टिप्पणी करना सक्षम प्राधिकरण द्वारा गलत पाया गया है, क्या प्रधानमंत्री अपने स्वयं के प्रतिमान पर खरे उतरेंगे और राष्ट्र से माफी मांगेगे?

यह सभी को पता है कि इतावली विचौलिया क्वात्रोची गांधी परिवार के बहुत करीबी था और कांग्रेस सरकार ने क्वात्रोची के गांधी परिवार की नजदीकियों के चलते प्रत्येक स्थिति में उसकी जमानत का प्रयास किया। प्रधानमंत्री और श्रीमती सोनिया गांधी द्वारा निम्नलिखित सवालों के उत्तर देने की आवश्यकता है :–

1. जुलाई 1993 में क्वात्रोची भारत से भाग गया था गिरफ्तारी से बचने के लिए उसे भागने की अनुमति दी गई जबकि उसी वर्ष उच्चतम न्यायालय ने विनचडढा की दलील खारिज कर दी थी तब श्री नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री भी थे।

भाजपा के संसद सदस्य, महासचिव एवं मुख्य राष्ट्रीय प्रवक्ता श्री रवि शंकर प्रसाद द्वारा जनवरी 04, 2011 को जारी प्रेस वक्तव्य

2. 1998 में जब राजग सत्ता में था तब पहली बार चार्ज शीट दाखिल की गई और नवम्बर 1999 में ट्रायल कोर्ट ने क्वात्रोची और अन्य दोषियों के खिलाफ गिरतारी वारंट जारी किया था। उसने गिरफ्तारी वांरट के विरूद्ध उच्चतम न्यायालय में अपील की और कोर्ट ने उसे सीबीआई (CBI) के सामने हाजिर होने को कहा उसने उपस्थित होने से मना कर दिया।
3. जुलाई 2003 में, तब राजग सरकार के निवेदन पर यू.के. ने क्वात्रोची के उस बैंक एकाउंट पर रोक लगा दी थी जिस एकाउंट में करदाताओ ं की राशि रिश्वत के रूप में जमा की गई थी। बड़े आश्चर्यजनक रूप से जब यूपीए सत्ता में आया, तब तत्कालीन कानून मंत्री श्री हंसराज भारद्धाज के निरीक्षण में, कुचक्र पर आधारित विधि सलाह के आधार पर तत्कालीन अतिरिक्त सालिस्टिर जनरल श्री बी. दत्ता लंदन गये और अधिकारियों के सामने यह कहा कि क्वात्रोची के विरूद्ध कोई मुकदमा लंबित नही है और उनके खाते से रोक हटा दी जानी चाहिए। ऐसा ही किया गया और करदाताओं का धन खाते से निकाला गया। यह किसके दवाब में किया गया ?
4. 2005 में बोफोर्स डील में हिन्दुजा के शामिल होने के दोष से बचने के दिल्ली हाइकोर्ट के आदेश के विरूद्ध सीबीआई की अपील को महान्यायवादी ने इंकार कर दिया। ऐसा क्यों किया गया, जबकि बोफोर्स मामले में दिल्ली हाइकोर्ट के सभी आदेशों को उच्चतम न्यायालय ने असंगत बताते हुए किनारे कर दिया था?
5. इन्हीं महान्यायवादी ने फिर एक कुचक्री सलाह दी कि क्योंकि दिल्ली हाइकोर्ट का आदेश अंतिम है इसलिए क्वात्रोची के विरूद्ध रेड कार्नर नोटिस जारी रखने का

कोई अर्थ नहीं है। यह ऐसा जानते हुए किया गया कि यहां तक कि हिन्दुजा मामले में कवात्रोची मामले पर कोई विचार ही नहीं किया गया। किसके दबाव में ऐसी कुचक्री सलाह दी गई ?

6. अर्जेंटीना के कोर्ट ने, अपील करने में जानबूझ कर विलम्ब किया गया क्योंकि दस्तावेजों को स्पेनिश भाषा में अनुवाद करने में समय लगाया गया और उसे भागने की अनुमति दी गई।
7. 2009 सितम्बर में, केन्द्र ने उच्चतम न्यायालय को अपने निर्णय के बारे में बताया कि क्वात्रोची के विरूद्ध मुकदमों को वापस ले लिया है। यह सभी बाते यह स्पष्ट संकेत देती है कि भारत सरकार की समूची मशीनरी विभिन्न स्थितियों में क्वात्रोची की सहायता करने और जमानत दिलवाने का प्रयास करती रही है। यह सब संरक्षण उन्हे गांधी परिवार की नजदीकियों के चलते मिला है। प्रधानमंत्री और श्रीमती सोनिया गांधी दोनों को देश के सामने यह बताना होगा कि उन्होंने ऐसा क्यों होने दिया ?

आयकर प्राधिकरण के निर्णय को दृष्टि में रखते हुए क्वात्रोची के खिलाफ पुनः मुकदमा शुरू करने और एसआईटी द्वारा जांच कराने की जरूरत है

अलगाववादी ताकतों के मंसूबे सफल नहीं होंगे : नितिन गडकरी

Hkkरतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नितिन गडकरी ने कलकत्ता में 'जहां हुए बलिदान मुकर्जी–वह कश्मीर हमारा है, कश्मीर जाएंगे–तिरंगा फहराएंगे, वंदेमातरम्, भारत माता की जय' जैसे राष्ट्रवादी नारों की गूंज के बीच भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अनुराग ठाकुर को राष्ट्रध्वज तिरंगा सौंपकर मोर्चा द्वारा आयोजित 'राष्ट्रीय एकता यात्रा' को रवाना किया। विदित हो कि राष्ट्रीय एकता व अखंडता को अक्षुण्ण रखने के उद्देश्य निकाली जा रही यह यात्रा देश के विभिन्न राज्यों से होती हुई 26 जनवरी 2011 को श्रीनगर पहुंचेगी, जहां श्री अनुराग ठाकुर लाल चौक में तिरंगा फहराएंगे।

युवाओं के प्रेरणास्रोत स्वामी विवेकानंद जयंती (12 जनवरी 2011) के दिन आयोजित इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री नितिन गडकरी ने कहा कि जम्मू और कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और अलगाववादी ताकतों के द्वारा इसे ''स्वतंत्रता या स्वायत्तता'' देने की मांग किए जाने पर भी स्वीकार नहीं किया जा सकता है। श्री गडकरी ने कहा कि यद्यपि जम्मू और काश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला तथा कुछ अलगाववादी भले ही 'यात्रा' का विरोध कर रहे हों, परन्तु यह प्रत्येक भारतीय नागरिक का मौलिक अधिकार है कि वह देश के किसी भी कोने पर राष्ट्रीय ध्वज फहराए। उन्होंने कहा कि हम मुस्लिम या अन्य किसी भी मजहबी समुदाय के हितों के खिलाफ नहीं हैं, परन्तु कांग्रेस है कि वह ''वोट–बैंक की राजनीति'' का खेल खेलते हुए गलत नीतियां अपनाकर लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रही है। उदाहरण के लिए देखिए कि वह बंगलादेशियों की अवैध घुसपैठ से स्थानीय असमिया लोगों की रोजी रोटी छीनती है तो उधर पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के हिंदुओं को वोट देने का अधिकार भी नहीं है और काश्मीरी पंडित की आवाज सुनी नहीं जाती है। उन्होंने यह भी कहा कि आज कश्मीर की प्रज्ज्वलनशील स्थिति का कारण भी पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की 'तुष्टिकरण की नीतियां' ही जिम्मेदार हैं। भाजयुमो के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अनुराग ठाकुर ने राष्ट्रीय एकता यात्रा को राष्ट्रीय महत्व का बताते हुए कहा कि इस यात्रा का उद्देश्य पवित्र है और इसे निकालने का मकसद है भारतीय एकता को मजबूती प्रदान करना। इस अवसर पर भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री श्री अनंत कुमार, भाजपा महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री स्मृति ईरानी, सांसद श्री चंदन मित्रा, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष श्री राहुल सिन्हा, युवा मोर्चा के राष्ट्रीय महासचिव श्री मनोरंजन मिश्र सहित अनेक वरिष्ठ भाजपा व भाजयुमो नेतागण उपस्थित थे। ■

यूपीए सरकार बोफोर्स मामले में अपराध-बोध से ग्रस्त

राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) ने 6 जनवरी 2011 को प्रधानमंत्री को ज्ञापन सौंपा, जिस पर कार्यकारी अध्यक्ष श्री लालकृष्ण आडवाणी, संयोजक श्री शरद यादव, लोकसभा में विपक्ष की नेता श्रीमती सुषमा स्वराज, राज्य सभा में विपक्ष के नेता श्री अरुण जेटली, राज्य सभा में जद(यू) नेता श्री शिवानंद तिवारी, शिवसेना के मुख्य सचेतक श्री ए.आर. अद्सुल एवं शिरोमणी अकाली दल के नेता श्री नरेश गुजराल ने हस्ताक्षर किए। हम ज्ञापन का पूरा पाठ यहां प्रकाशित कर रहे हैं:–

fi:; iekkue=h th]

हाल ही में उच्च स्थानों पर भ्रष्टाचार सम्बंधी अनेक मामलों का पर्दाफाश सार्वजनिक रूप से हुआ है। 2जी स्पैक्ट्रम के आवंटन सम्बंधी घोटाले से देश के खजाने को अपार हानि का पर्दाफाश भी हुआ है। नई दिल्ली के कॉमनवेल्थ खेलों से जुड़े संगठन के घोटालों के कारण अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र का यह संगठन दागदार बन चुका है और इसके आसपास नकारात्मक माहौल पैदा हुआ है। बिचौलियों तथा कर–अपवंचकों द्वारा बोफोर्स मामले में प्राप्त दलाली पर कर–उगाही करने वाले आयकर अपीलीय ट्राइब्युनल के आदेश ने निश्चित रूप से इस रहस्य को खोलकर रख दिया है कि तेईस वर्षों से इस राशि का लाभ उठाने वालों तथा उनके राजनैतिक आकाओं ने दलाली की अदायगी को छुपा कर रखा है। इससे यह भी निश्चित सिद्ध हो जाता है कि तत्कालीन प्रधानमंत्री के परिवार के करीबी लोग दलाली पाने वालों में शामिल थे।

यह बात कहने की भी आवश्यकता नहीं रह जाती है कि इस प्रकार की भ्रष्ट राशि का स्थान भी भारत में ही हुआ हो, यह आवश्यक नहीं है। इस अपराध से अर्जित राशि और भ्रष्टाचार युक्त यह कलंकित राशि के स्थान में विश्व का कोई भी हिस्सा शामिल हो सकता है। इस राशि को ठिकाने लगाने का प्रयोजन दो प्रकार का रहा जिससे इस दूषित भ्रष्ट राशि को छिपाया जा सके और साथ ही करों से बचा जा सके। विश्व के विभिन्न भागों में स्थित 'टैक्सहेवन' वाले स्थानों ने इस राशि को सुरक्षित बना दिया। इन 'टैक्स हेवन' क्षेत्रों में धन को रखने का प्रयोजन यही रहा कि इन क्षेत्रों में बैंकिंग प्रणाली के कारण इस धन राशि पर पर्दा पड़ा रहता है और इससे खाता धारकों को अपने खातों तथा इनके लाभार्थियों को सुरक्षा मिली रहती है। इस प्रकार के क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था भ्रष्ट राशि के स्थानों को जन्म देती है।

यह कोई छुपी बात नहीं है कि कुछ बिजनसमैनों, हवाला कारोबारियों और निषिद्ध एवं गैर–कानूनी कारोबार करने वाले लोगों तथा साथ में मिले राजनेताओं तथा सिविल अधिकारियों ने इस प्रकार के 'टैक्स हेवन' क्षेत्रों में अपनी कुछ सम्पत्तियां छुपा कर रखी हुई हैं।

पारम्परिक ढंग से काम करने वाली किसी प्रणाली के अन्तर्गत इन खातों के पीछे के गोपनीय पर्दा उठाना काफी कठिन ही होता है। पारम्परिक रूप से तो यह दो पक्षों के बीच व्यवस्था रहती है कि वे 'ड्यूअलक्रिमिनिलिटी' के सिद्धांत के बाद कुछ पक्ष ऐसे हैं जिन्होंने जांचकर्ताओं को ऐसे कुछ टैक्स हेवन क्षेत्रों में सहयोग देने का आश्वासन दिया है। परन्तु, दूसरे कुछ टैक्स हेवन क्षेत्रों ने तो उनके पास अपराध के लाभ के ऐसे पैसे जमा होने पर भी सहयोग से मना कर दिया, जबकि यह पैसा दोनों देशों में अपराध के लाभ का पैसा माना जाता है।

संयुक्त राष्ट्र संघ ने भ्रष्टाचार के विरूद्ध प्रस्ताव पारित किया है। 240 देशों में से इस प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करने वालों में से 14 देश ऐसे भी जिन्होंने इस प्रस्ताव को अपने देश में अनुमोदित तक नहीं किया है और भारत उनमें से एक है। विश्व के अनेक देशों ने स्विस सरकार पर दबाव डाला है कि वह विदेशों से आए जमा धन का सार्वजनिक करे। अमेरिका, जर्मनी तथा कई अन्य देशों को तो

बिचौलियों तथा कर–अपवंचकों द्वारा बोफोर्स मामले में प्राप्त दलाली पर कर–उगाही करने वाले आयकर अपीलीय ट्राइब्युनल के आदेश ने निश्चित रूप से इस रहस्य को खोलकर रख दिया है कि तेईस वर्षों से इस राशि का लाभ उठाने वालों तथा उनके राजनैतिक आकाओं ने दलाली की अदायगी को छुपा कर रखा है। इससे यह भी निश्चित सिद्ध हो जाता है कि तत्कालीन प्रधानमंत्री के परिवार के करीबी लोग दलाली पाने वालों में शामिल थे।

स्विट्जरलैण्ड से खाताधारकों के लाभार्थियों की सूची मिल चुकी है। परन्तु भारत ने ऐसा कोई सक्रिय कदम नहीं उठाया है। 'राजग' के कार्यकारी अध्यक्ष ने इस मुद्दे पर एक कार्यदल का गठन किया था, जिसने अपनी एक विस्तृत रिपोर्ट पेश की है, जिसमें कई प्रमुख व्यक्ति सम्मिलित किए गए थे, जिसकी सिफारिशों की एक प्रति संलग्न की जा रही है।

हमारी आशंका है कि यूपीए सरकार इस मोर्चे पर कोई सक्रिय कदम उठाने से हिचकिचा रही है जिसके पीछे उसका अपना आत्म–अपराध बोध का भय सता रहा है। आखिर, 'तेल के लिए खाद्य' घोटाले में संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा नियुक्त वोल्कर समिति की रिपोर्ट में कांग्रेस पार्टी के एक लाभार्थी होने का नाम शामिल है। हमारी जांचकर्ता एजेंसियों और हमारी राजस्व एजेंसियों की जांच ने यह बात निश्चित और निर्णायक रूप से सिद्ध कर दी है कि बोफोर्स घूस मामले में दलाली खाने वाले लाभार्थियों में, जैसाकि आईटीएटी के आदेश में प्रगट होता है, निश्चित और पूर्ण रूप से सिद्ध कर दी है कि ओत्तावियो क्वात्रोची ने एई सर्विसेज और कोलबार इंवेस्मेंट जैसी प्रमुख कम्पनियों के माध्यम से पैसा खाया। ओत्तावियो क्वात्रोची और उनकी पत्नी मारिया के कांग्रेस पार्टी के प्रथम परिवार के साथ सम्बंध सभी लोग जानते हैं और इस पर कोई विवाद नहीं है।

स्विस जर्नल 'श्विजर इल्लस्ट्रिटे' के 19.11.91 के अंक में प्रकाशित एक अन्वेषणकारी रिपोर्ट में तीसरे देश के 14 वैश्विक नेताओं के स्विट्जरलैण्ड में खाते होने का नाम है। इनमें पूर्व भारत के प्रधानमंत्री का भी नाम शामिल है। इस रिपोर्ट से किसी भी को इंकार नहीं है। डॉ. येजेनिया अल्बर्ट द्वारा लिखित 'दि स्टेट विदिन ए स्टेट–दि केजीबी होल्ड आन रशिया इन पास्ट एंड फ्यूचर' पुस्तक में अद्‌भुत रहस्योद्‌घाटन करते हुए लिखा गया है कि भारत के पूर्व प्रधानमंत्री और उनके परिवार ने रूस के साथ वाणिज्यिक सौदों से लाभ अर्जित किए थे।

ये लेखों और पुस्तकों में प्रकाशित शोधकर्ता–लेख हैं। जांच के इन लक्ष्यों में जो आरोप लगे हैं, उन्हें कभी भी औपचारिक रूप से इंकार नहीं किया गया और न ही इनके खिलाफ अभियोजित प्रकाशनों के खिलाफ कोई कार्रवाई की गई है। सरकार के लिए यह एक महत्वपूर्ण बात है कि किसी भी भूत और वर्तमान के भारत एवं उसके नेताओं के उज्ज्वल नाम पर, जिसमें कोई भी पूर्व प्रधानमंत्री का भी नाम शामिल रहता है, धब्बा न लगे। अतः, या तो इन आरोपों का प्रभावकारी रूप से खंडन किया जाए या उनकी जांच की जाए।

एनडीए के कार्यकारी अध्यक्ष श्री लालकृष्ण आडवाणी तथा एनडीए के विभिन्न घटकों ने भी अनेक अवसरों पर इस धनराशि को खोज निकालने में भारत सरकार की सक्रिय भूमिका के मुद्दे को उठाया है। हमारा प्रमुख प्रयोजन यही रहा है कि भ्रष्टाचार खत्म होना चाहिए या कम से कम इसे निष्क्रिय तो बनाया ही जाए। प्रधानमंत्री ने 2009 चुनावों में साफ तौर पर कहा था कि यूपीए चुनाव सम्पन्न होने के 100 दिनों के अंदर इस अपराधपूर्ण–धनराशि खोज निकालने के लिए कारगर कदम उठाएगी। दुख की बात है कि इस बारे में यूपीए सरकार भी भूमिका अत्यंत निराशाजनक है।

अतः यह महत्वपूर्ण और आवश्यक है कि भारत में सार्वजनिक जीवन में फैल रही अविश्वसनीयता के इस संदेहपूर्ण वातावरण को हटाया जाए। यह तभी हो सकता है जब इन सभी मामलों की जांच हो और सच्चाई खोज निकाली जाए। सच्चाई का तभी पता चलेगा जब भारत सरकार कार्यदल की रिपोर्ट में सुझाए गए सक्रिय कदम उठाएगी और साथ ही भारतीयों द्वारा विदेश में जमा धन राशियों के ब्यौरे मालूम करेगी। ■

भाजपा कार्यसमिति ने अलग तेलंगाना राज्य की मांग की

8 tuojh dk xokgkVh e vk;kftr jk"Vh; dk;dkfj.kh cBd e fuEufyf[kr oDr0; ikfjr fd;k x;kA

भाजपा अलग तेलंगाना राज्य बनाने में यूपीए सरकार द्वारा किए जा रहे रवैये पर अपनी हताशा व्यक्त करती है। भाजपा का मानना है कि इस क्षेत्र के लोगों द्वारा तेलंगाना निर्माण की आशा करना वैध और सही है।

छोटे राज्यों के निर्माण करने से बेहतर प्रशासनिक इकाई कायम हो सकेगी जिससे इस क्षेत्र के आर्थिक विकास में तेजी आएगी। इस क्षेत्र को एक राज्य के रूप में तेलंगाना निर्माण की आवश्यकता है और जिस छह विकल्पों की संभावना पर विचार किया जा रहा है, उससे काम नहीं चल सकता है।

भाजपा की मांग है कि तेलंगाना राज्य के निर्माण के लिए संसद में विधेयक पेश करना चाहिए ताकि इसे शीघ्रातिशीघ्र पारित किया जा सके। ■